जनता के गोठ

Website- https://www.jantakegoth.com

● वर्ष -01 ● अंक- 312 ● रायपुर, मंगलवार 03 नवम्बर 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ- 12 ● मूल्य- 2 रुपया ● संपादक- शुभम वर्मा ● PRGI Reg No : CTBIL/25/A1787

पहला कॉलम

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, गोलीबारी में कुकी समुदाय के 3 लोगों की मौत

इंफाल। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। सुबह नोनी जिले के पहाड़ी गांव केकरू नगा में दो विरोधी गुटों के बीच हुई भीषण गोलीबारी में कुकी समुदाय के तीन लोगों की मौत हो गई। दोनों पक्षों के बीच कई घंटों तक गोलीबारी होती रही। पुलिस ने भी घटना में तीन लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। अधिकारियों के अनुसार, मामले की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। कुकी आदिवासी संगठन कुकी इनपी मणिपुर (केआईएम) ने आरोप लगाया है कि तीनों कुकी युवकों की हत्या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम इसाक मुइवा (एनएस सीएन आईएम) और जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ-के) के कामसन गुट के सशस्त्र सदस्यों ने की है। संगठन ने सरकार से घटना में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है।

दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को गुवाहाटी तक बढ़ाने की मंजूरी

गुवाहाटी। केंद्र ने प्रस्तावित दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को गुवाहाटी तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा. मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की हरी झंडी का जश्न मनाते हुए सीएम सरमा ने एक्स पर विपक्ष पर राजनीतिक कटाक्ष किया. सरमा ने लिखा, इसीलिए, मोदी कहीं नहीं जाएंगे! (यही कारण है कि मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं!) यह टिप्पणी शायद हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर हुए विवाद का तीखा जवाब है. यह टिप्पणी एक कार्यक्रम के बाद आई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पद नहीं छोड़ेंगे. सरमा ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा, गुवाहाटी-दिल्ली 8 घंटे से कम में? हाँ! उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का गुवाहाटी तक विस्तार पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है. उन्होंने कहा, शुरू में कॉरिडोर सिलीगुड़ी में खत्म होना था.

राजस्थान के आईएएस-आईपीएस दंपति के पास 40 आलीशान विला

जयपुर। राजस्थान के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी पत्नी प्रशाखा माथुर के संपत्ति सौदों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाया और बाद में उसी कंपनी के दो रिसॉर्ट में अपने परिवार के नाम पर 40 विला और कॉटेज खरीद लिए। मामला सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने दंपती के खिलाफ जांच शुरू करा दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी और उनके परिवार ने करीब ढाई साल के दौरान अनंता समूह के दो रिसॉर्ट में कुल 40 संपत्तियां 6.16 करोड़ रुपये में खरीदीं।

हैदराबाद में बीजेपी की महा पदयात्रा

रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ' नहीं 'घुसपैठिये बचाओ' रैली थी

हैदराबाद। एजेंसी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 नवंबर को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी की महा पदयात्रा निकाली। हाथ में तिरंगा लेकर निकले शाह के साथ हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक भी शामिल हुए। यह पदयात्रा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी सियासी टकराव के बीच निकाली गई। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस स्क्रुक्र प्रक्रिया का विरोध करके घुसपैठियों को बचाना चाहती है। शाह ने साफ कहा कि बीजेपी एक-एक घुसपैठिये का नाम मतदाता सूची से हटवाएगी और उन्हें देश से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। पदयात्रा में शामिल होने से पहले अमित शाह ने हैदराबाद के प्रसिद्ध भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए एसआईआर घुसपैठ और कांग्रेस की राजनीति को लेकर विपक्ष पर कई तीखे हमले किए। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा।



उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहे जितनी कोशिश कर लें, बीजेपी यह सुनिश्चित करेगी कि एक-एक घुसपैठिये का नाम मतदाता सूची से हटाया जाए। शाह ने कहा, राहुल जी, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि एक-एक घुसपैठिये को मतदाता सूची से हटा दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही है, क्योंकि इससे उसके कथित वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। अमित शाह ने राहुल गांधी के उस दावे पर भी सवाल उठाए, जिसमें बीजेपी की चुनावी जीत को एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ने की बात कही गई थी। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी जीते थे, जबकि उस समय एसआईआर जैसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही थी। उन्होंने कहा, मोदी जी 2019 में भी जीते थे। तब कोई एसआईआर नहीं था। क्या मोदी जी जीते या नहीं? वे भारत के मतदाताओं की वजह से जीते। शाह ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में बीजेपी की जीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में पार्टी को जनता का भारी समर्थन मिला है।

आज रायपुर आएंगे केंद्रीय गृहमंत्री शाह राज्योत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे एक निजी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वे दोपहर 3 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सीधे अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने जाएंगे। इसके बाद शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन 'नक्सल मुक्त राज्य' की थीम पर किया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए समयसीमा निर्धारित करने की घोषणा की थी। वहीं, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि राज्योत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों और लोक नर्तकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदेश की लोककला और स्थानीय प्रतिभाओं को बड़े मंच पर अवसर देना है। उन्होंने बताया कि जनता और युवाओं की मांग को देखते हुए देश के तीन चर्चित बाहरी कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान

न्याय के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.....सीजेआई....

नई दिल्ली/ एजेंसी



भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायिक प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में लंबित मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले याचिकाकर्ताओं की बढ़ती संख्या न्याय व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश पर विचार करने का मौका देती है। सीजेआई ने सवाल उठाया कि क्या जरूरी मामलों की पहचान और सुनवाई की तारीख तय करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। रविवार को कोच्चि में केरल हाई कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में सीजेआई सूर्यकांत ने यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को समय पर न्याय पाने के लिए दिल्ली तक आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भारत की संवैधानिक न्याय व्यवस्था सिर्फ नई दिल्ली तक सीमित नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हाई कोर्ट की संस्थागत स्वतंत्रता और अपने मामलों की सुनवाई का क्रम तय करने के अधिकार का सम्मान किया है। इसके बावजूद हाई कोर्ट में लंबित मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले याचिकाकर्ताओं की बढ़ती संख्या पर विचार करना जरूरी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या जरूरी मामलों की पहचान बेहतर तरीके से की जा सकती है? क्या सुनवाई की तारीख तय करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सकता है? क्या तकनीक की मदद से उन मामलों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिनमें देरी से किसी पक्ष को ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई संभव न हो? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देशभर में मौजूद 25 हाई कोर्ट भारतीय न्याय व्यवस्था की मजबूती का आधार हैं।

दिल्ली में ग्रीन पटाखों को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने बिक्री से इस्तेमाल तक तय किए नियम

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के मौके पर 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इसके लिए समय और जगह तय की गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, लोग इन दो दिनों में सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। 9 नवंबर से पटाखों पर फिर से पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो जाएगा। कोर्ट ने साफ किया है कि केवल प्रमाणित पर्यावरण-अनुकूल यानी ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी यही नियम लागू रहेगा। इन सभी जगहों को पटाखा-मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा और इसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इस फैसले के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि साल 2024 में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बावजूद एक्यूआई में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला था। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्ण प्रतिबंध से प्रदूषण कम करने का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं।



ग्रीन पटाखों की बिक्री और पहचान पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कई निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सभी जिलों के कलेक्टरों और आयुक्तों को पुलिस अधीक्षकों के साथ मिलकर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित जगहें तय करने को कहा है। इन बिक्री केंद्रों और दुकानों पर जागरूकता से जुड़े बैनर लगाने होंगे। इन पर यह जानकारी भी देनी होगी कि ग्राहक से प्रमाणित असली ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे कर सकते हैं।

भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन तैयार हो रही, 280 किमी प्रति घंटे होगी अधिकतम परीक्षण गति

नई दिल्ली। भारत उच्च गति रेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना के लिए बेंगलुरु स्थित बीईएमएल के कारखाने में तैयार की जा रही है। इस ट्रेन को भारतीय परिस्थितियों, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार, ट्रेन की अधिकतम परीक्षण गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा और परिचालन गति 249 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

60 किमी रफ्तार से चलेंगी हवाएं

छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रहा तूफान मुरासु, 3 और 4 नवंबर को होगी बारिश..

रायपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान मुरासु का असर अब छत्तीसगढ़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम प्रणाली के प्रभाव से प्रदेश में 3 और 4 नवंबर को तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है। तूफान के प्रभाव से पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। 2 और 3 नवंबर को कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाओं और गरज-चमक की भी चेतावनी दी गई है। वहीं तमिलनाडु में भी जोरदार



बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ और दक्षिण मौसम प्रणाली आगे बढ़ने के ओडिशा में इसका प्रभाव साथ 3 और 4 नवंबर को दिखाई दे सकता है। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और आकाशीय बिजली की स्थिति बन सकती है। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने और झोंकों के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी रायपुर में भी मौसम का मिजाज बदलने लगा है।



बलौदाबाजार के जंगल में खून से लथपथ मिला अज्ञात युवक का शव, धारदार हथियार से हमले की आशंका।

अमेरिका में बिजनेस जेट क्रैश

9 लोगों की मौत,आग का गोला बना विमान

नई दिल्ली। अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा में रविवार को एक बड़ा विमान हादसा पेश आया। ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहामास के लिए उड़ान भरने वाला एक निजी बिजनेस जेट तकनीकी खराबी के चलते अनियंत्रित होकर जमीन पर आ गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान में तुरंत भीषण आग लग गई और चारों तरफ घना काला धुआं फैल गया। इस भयावह दुर्घटना में विमान में सवार सभी नौ लोगों की मौके पर ही जान चली गई। अमेरिकी विमानन एजेंसियां अब हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने में जुट गई हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त विमान 'लियरजेट 60' था, जिसका टेल नंबर एन 722बीडी दर्ज है। ऑस्टिन-बर्गस्ट्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता जिम रेनॉल्ड्स ने इसे एक अत्यंत दुखद और बड़ी त्रासदी करार दिया।

11 हजार वोल्ट की लाइन से टकराई रोड़ी मिक्सर मशीन

दर्दनाक हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, पांच लोग झुलसकर घायल

झुंझुनू। एजेंसी

राजस्थान के झुंझुनू जिले के छापोली गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग झुलसकर घायल हो गए। गांव में जनसहयोग से सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान कंक्रीट तैयार करने के लिए लगाई गई रोड़ी मिक्सर मशीन ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। इससे पूरी मशीन में करंट फैल गया और उसके आसपास काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। झुंझुनू जिला कलेक्टर अरुण गर्ग से मिली जानकारी के अनुसार, उदयपुरवाटी क्षेत्र के छापोली गांव में स्थानीय ग्रामीण आपसी जनसहयोग से सड़क का निर्माण करवा रहे थे। यह काम कदम कुंड की ओर जाने वाले मार्ग पर चल रहा था। सड़क निर्माण के लिए कंक्रीट तैयार करने के उद्देश्य से मौके पर रोड़ी मिक्सर मशीन लगाई गई थी। इसी दौरान मशीन का ऊपरी हिस्सा असावधानीवश ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया। बिजली के तार से छूते ही धातु की पूरी मशीन में करंट फैल गया। इसकी चपेट में आसपास काम कर रहे मजदूर आ गए। अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। करंट



का झटका इतना तेज था कि 5 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ग्रामीणों और वहां मौजूद लोगों ने बिजली आपूर्ति बंद करवाने के प्रयास किए और घायलों को बचाने में जुट गए। झुलसे हुए मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उपचार के दौरान 3 अन्य मजदूरों की भी मौत हो गई। इस तरह हादसे में मृतकों की कुल संख्या 8 पहुंच गई है। वहीं, 5 अन्य लोग करंट से झुलसकर घायल हुए हैं। सभी का उपचार जारी है। इस हादसे में हालेड़ा मंडावरा निवासी एक ही परिवार के चार लोगों की जान चली गई। मृतकों में हरिराम गुर्जर (30), मंगलचंद गुर्जर (22), कालूराम गुर्जर (29) और पवन गुर्जर (23) शामिल हैं। इसके अलावा छापोली निवासी विष्णु सैनी (38), सुरेंद्र उर्फ सुरेश सैनी (30), मुकेश सैनी (27) और फतेहचंद सैनी (32) की भी मौत हुई है। हादसे में छापोली निवासी महेंद्र सैनी, गीता देवी (45), संतरा देवी (35), गिदाराम सैनी (45) और मंजू देवी (38) घायल हुए हैं।

13 अगस्त से टूटी पुलिया, 20 पंचायतों का रास्ता बंद; ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

अंधरक्कां नदी पर क्षतिग्रस्त पुलिया से स्कूली बच्चों, किसानों और व्यापारियों की बढ़ी परेशानी, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

जाहिद अंसारी- सूरजपुर।

प्रतापपुर। विकासखंड प्रतापपुर के ग्राम धोंधा में अंधरक्कां नदी पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त होने से करीब 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया है। 13 अगस्त 2026 को हुई अतिवृष्टि के दौरान पुलिया टूटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद से आवागमन प्रभावित है, लेकिन अब तक मरम्मत की दिशा में ठोस पहल नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हालात यह हैं कि स्कूली बच्चों से लेकर किसानों और व्यापारियों तक को रोजमर्रा के कामकाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

2010-11 में बनी पुलिया, अतिवृष्टि ने पहुंचाया नुकसान

ग्रामीणों के अनुसार अंधरक्कां नदी पर वर्ष 2010-11 में पुलिया का निर्माण कराया गया था। यह पुलिया आसपास के गांवों के लिए आवागमन का प्रमुख माध्यम थी। लेकिन 13 अगस्त को हुई अतिवृष्टि के दौरान पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद से क्षेत्र के लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया से होकर लगभग 20 ग्राम पंचायतों के लोग आवागमन करते थे। इसके क्षतिग्रस्त होने से अब लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बच्चों की पढ़ाई से लेकर किसानों के कारोबार तक प्रभावित

पुलिया क्षतिग्रस्त होने का असर केवल आवागमन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव ग्रामीण जनजीवन पर पड़ रहा है। स्कूली छात्र-छात्राओं को स्कूल आने-जाने में परेशानी हो रही है। वहीं किसानों को कृषि कार्यों और



अपनी उपज के परिवहन में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। व्यापारियों के लिए भी क्षेत्र में आवागमन और कारोबार करना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते पुलिया की मरम्मत नहीं कराई गई तो परेशानियां और बढ़ सकती हैं।

प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी समाधान नहीं ग्रामीणों के मुताबिक पुलिया क्षतिग्रस्त होने और आवागमन की समस्या से जिला प्रशासन तथा स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वैकल्पिक रास्ते की समुचित व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

एसडीएम को ज्ञापन, 15 दिन का अल्टीमेटम

समस्या से परेशान ग्रामीणों ने अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) प्रतापपुर को ज्ञापन सौंपकर क्षतिग्रस्त पुलिया की शीघ्र मरम्मत कराने और आवागमन बहाल करने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि निर्धारित समयावधि में समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक पहल नहीं की गई तो धरना-प्रदर्शन सहित आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

अब प्रशासन की पहल का इंतजार

करीब 20 ग्राम पंचायतों के आवागमन से जुड़ी इस समस्या ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिया की तकनीकी जांच कराए और मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करे, ताकि स्कूली बच्चों, किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को राहत मिल सके। अब देखना होगा कि ग्रामीणों के 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है।

बाढ़ प्रभावित बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आए बड़ेमुरमा के विद्यार्थी, 8 हजार रुपये की जुटाई सहायता राशि

जूनियर रेडक्रॉस सोसायटी की पहल से 300 से अधिक बच्चों को मिली पाठ्य सामग्री, जिला शिक्षा अधिकारी ने साक्षी कश्यप को किया सम्मानित



ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ जगदलपुर। बस्तर जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ेमुरमा की जूनियर रेडक्रॉस सोसायटी के विद्यार्थियों ने मानवीय पहल की है। विद्यार्थियों ने स्वयं 8 हजार रुपये एकत्रित कर बाढ़ प्रभावित गांवों के 300 से अधिक जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की। इस सेवा कार्य के लिए जिला शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल ने छात्रा साक्षी कश्यप को सम्मानित किया। सहायक नोडल अधिकारी मनीष अहीर के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की टीम ने बकावंड विकासखंड के कोहकापाल, लिटिगुड़ा, कुरुषपाल एवं मालगांव में लगभग 300 बच्चों को कॉपी, पेन और पेंसिल की स्टेशनरी किट वितरित की। वहीं बस्तर विकासखंड के ग्राम कुड़कानार में 30 बच्चों को स्टेशनरी किट के साथ बिस्किट भी प्रदान किए गए। इस सेवा कार्य में विद्यालय के प्राचार्य जीवन दास सहित कांता प्रसाद वैद्य, समीर नाग, डीके देवांगन, राजेंद्र धुर्वे, पुनीत राम फरदिया, मोहित, राजेश गुप्ता, तुलादास मानिकपुरी, नीलमणि साहू, जितेंद्र साहू, राजेश्वरी, गुड़िया, सरोज, अंजली एवं नीलीमा सहित अन्य सदस्यों का सहयोग रहा। जिला जूनियर रेडक्रॉस नोडल अधिकारी एलेक्स जेंडर का भी मार्गदर्शन मिला।

विद्यार्थियों की इस पहल ने आपदा के समय जरूरतमंदों की सहायता, शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया।

3282 ग्रामीणों के स्वास्थ्य का सहारा खुद बीमार, गंगौटी के आरोग्य मंदिर में दवाओं का टोटा!

मरीजों को न पर्ची मिल रही, न जरूरी दवाएं; 5 नवंबर से सीएचओ की अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर सवाल

जाहिद अंसारी, सूरजपुर।

भैयाथान। ग्रामीणों को गांव में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सरकारी दावे भैयाथान विकासखंड के ग्राम गंगौटी में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। यहां संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) खुद बदहाली का शिकार है। केंद्र में जरूरी दवाओं की कमी के चलते इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कहीं मरीजों को दवा नहीं मिल रही, तो कहीं डॉक्टर की पर्ची तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसे में सामान्य बुखार, दर्द और उल्टी-दस्त जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी ग्रामीणों को 12 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आगामी 5 नवंबर से सीएचओ के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर और बड़ा संकट खड़ा कर दिया है।

तीन गांवों की 3282 आबादी, स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर परेशानी

शासकीय आंकड़ों के अनुसार गंगौटी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के कार्यक्षेत्र में ग्राम पंचायत गंगौटी सहित डबरीपारा और खुटारापारा के ग्रामीण आते हैं। इनमें गंगौटी की आबादी 1809, डबरीपारा की 1045 और खुटारापारा की 428 है। इस तरह कुल 3282 ग्रामीणों की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी इसी केंद्र पर है। गर्भवती महिलाओं की जांच, बच्चों का टीकाकरण, मौसमी बीमारियों का उपचार और बीपी-शुगर जैसी एनसीडी जांच के लिए ग्रामीण इसी केंद्र पर निर्भर हैं। लेकिन दवाओं की कथित किल्लत के कारण ग्रामीणों को निजी मेडिकल दुकानों और दूरस्थ अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है।

मरीजों का आरोप, रजिस्टर में नाम दर्ज कर लौटा देते हैं कर्मचारी- स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र में इलाज के लिए पहुंचने पर अक्सर जरूरी दवाएं



उपलब्ध नहीं रहतीं। मरीजों को न तो उपचार संबंधी पर्ची दी जाती है और न ही उपलब्ध दवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाती है। केवल रजिस्टर में नाम और पता दर्ज कर दवा खत्म होने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि केंद्र में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं तो मरीजों को वैकल्पिक उपचार की व्यवस्था और उचित मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया जाता?

पांच साल के बच्चे को इलाज के लिए जाना पड़ा 15 किमी दूर- केंद्र की बदहाल व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में बुखार और मौसमी बीमारी से पीड़ित एक पांच वर्षीय बच्चे सहित 20 वर्षीय युवक को उपचार के लिए केंद्र पहुंचने पर जरूरी दवाएं नहीं मिल सकीं। ग्रामीणों के मुताबिक एक मरीज को केवल पैरासिटामोल की गोली दी गई, जबकि अन्य को स्टॉक खत्म होने की बात कहकर लौटा दिया गया। पांच वर्षीय बच्चे के परिजनों को बेहतर उपचार के लिए उसे करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा। गांव में स्वास्थ्य केंद्र मौजूद होने के बावजूद छोटे बच्चे को इलाज के लिए इतनी दूर ले जाने की मजबूरी ने स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है।

मितानिनों की दवा पेटियां भी खाली- गांवों में घर-घर पहुंचकर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली मितानिनों की दवा किट भी प्रभावित होने की बात सामने आई है। मितानिनों को आवश्यक दवाएं इसी केंद्र से उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन जब मुख्य केंद्र में ही दवाओं की कमी है, तो मितानिनों को भी ओआरएस, पैरासिटामोल और उल्टी-दस्त जैसी सामान्य बीमारियों की दवाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही मिलने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा भी प्रभावित हो रही है।

एएनएम दूसरे अस्पताल में अटैच, केंद्र की जिम्मेदारी एक सीएचओ पर- केंद्र की व्यवस्था को लेकर एक और गंभीर सवाल सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां पदस्थ एएनएम को वर्षों पहले दूसरे स्वास्थ्य संस्थान में अटैच कर दिया गया है। वहीं दो आरएचओ का अधिकांश काम फील्ड में टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच और स्वास्थ्य सर्वे से जुड़ा है। ऐसे में सीएचओ की अनुपस्थिति में केंद्र में ताला लगने की स्थिति निर्मित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

राज्योत्सव 2026 के अवसर पर ATMA योजना अंतर्गत कृषकों का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित

जनता के गोठ/ओंकार साहू

बलौदाबाजार। एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (ATMA) योजना अंतर्गत राज्य के भीतर कृषक शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत 1 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस एवं राज्योत्सव के अवसर पर विकासखंड सिमगा के कृषकों को नया रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल के भ्रमण हेतु रवाना किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड सिमगा अनिल कुमार दीवान के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सिमगा से कृषकों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भ्रमण दल मे संतोषदास मानिकपुरी (RAEO) एवं आत्मा



योजना के विकासखंड तकनीकी प्रबंधक (ब्लॉक्रू) कु.राधिका रॉय, सहायक तकनीकी प्रबंधक (ब्लॉक्रू)योगेश कुमार साय एवं श्री.चंद्रपाल जोगी, कृषक मित्र समयलाल साहू एवं शेषनारायण साहू सहित विकासखंड सिमगा के कृषकगण शामिल हुए। इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य कृषकों को राज्योत्सव के माध्यम से छत्तीसगढ़ की कृषि, उन्नत कृषि तकनीकों, नवीन योजनाओं, कृषि नवाचारों एवं विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शित उपलब्धियों से अवगत कराना तथा आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रकार के भ्रमण से कृषकों को नवीन तकनीकी जानकारी प्राप्त होने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों एवं संभावनाओं को समझने का अवसर मिलता है।

तक्षशिला कंप्यूटर सेंटर में प्रतिभाओं का सम्मान, हुनरमंद विद्यार्थियों को मिला मंच

जनता के गोठ/ओंकार साहू

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को तक्षशिला कंप्यूटर सेंटर सिमगा में छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राखी निर्माण, मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

सेंटर संचालक दीपक साहू ने कहा कि शिक्षा के साथ रचनात्मकता, नवाचार और व्यावहारिक कौशल का ज्ञान भी जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (ह्श्वक्र) भी कौशल आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।

मुख्य अतिथि पारस पाटकर ने विद्यार्थियों को मेहनत और संकल्प



के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। विशिष्ट अतिथि चंद्रप्रकाश टोडे ने दीपक साहू के शैक्षणिक प्रयासों की सराहना की, वहीं सतनामी समाज परिक्षेत्र अध्यक्ष शत्रुघन मार्कण्डेय ने युवाओं को छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी बनने का संदेश दिया।

कार्यक्रम में नए विद्यार्थियों को बैग एवं पुराने छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया गया। छात्र-छात्राओं ने राजकीय गीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मंत्री टंकराम वर्मा के जिला पंचायत रायपुर प्रतिनिधि गिरीश साहू की विशेष उपस्थिति रही।

कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, राम कोसले, सदानंद साहू, हिमांशु देवांगन, तारणी साहू सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंटकर आभार व्यक्त किया गया।

विदेश में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार के के.के. पार्क में बनाया बंधक, साइबर ठगी कराने वाली महिला गिरफ्तार

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को म्यांमार ले जाने और वहां बंधक बनाकर साइबर ठगी कराने के मामले में दर्री पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता को बैंकॉक में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी दिलाने का लालच दिया गया था। इसके बाद उसे थाईलैंड के रास्ते म्यांमार के कुख्यात 'केके पार्क ' पहुंचाया गया, जहां कथित तौर पर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने के लिए मजबूर किया गया।

पुलिस ने आरोपी स्नेहा भथलाल बडोले (35), निवासी गोंदिया, महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मामले में अन्य आरोपियों और गिरोह के डिजिटल व वित्तीय नेटवर्क की जांच जारी है।

कोरबा पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दर्री निवासी पीड़िता ने फेसबुक पर बैंकॉक में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी का विज्ञापन देखा था। इसमें करीब 30 हजार थाई भाट प्रतिमाह वेतन देने की बात कही गई थी। नौकरी पाने की उम्मीद में उसने विज्ञापन से जुड़े लोगों से संपर्क किया। आरोप है कि महिला लीजा और उसके साथियों ने पीड़िता को पहले बेंगलुरु बुलाया। वहां से उसे विमान के जरिए थाईलैंड ले जाया गया। इसके बाद सीमा पार कराकर म्यांमार के केके पार्क पहुंचा दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, म्यांमार पहुंचने के बाद पीड़िता का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि गिरोह के सदस्य उसे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने के लिए मजबूर करते थे। इस तरह नौकरी के नाम पर शुरू हुआ मामला कथित तौर पर साइबर अपराध के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा निकला।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन की मदद से पीड़िता को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। इसके बाद उसने दर्री थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर थाना दर्री में अपराध क्रमांक 331/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 143(2) और 146 में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने विवेचना के दौरान कथित संलिप्तता सामने आने पर स्नेहा भथलाल बडोले को गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड प्राप्त की गई है। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका और गिरोह के डिजिटल तथा वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रही है।

कोरबा पुलिस ने साइबर जागरूकता अभियान के तहत लोगों से अपील की है कि वे विदेश में नौकरी के आकर्षक प्रस्तावों की जांच किए बिना उन पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर मिले नौकरी के विज्ञापनों की सत्यता जांचना और पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज अनजान लोगों को नहीं सौंपना जरूरी है।

मदननगर खदान से संवर सकता है युवाओं का भविष्य, रोजगार और विकास की उम्मीदों पर टिकी निगाहें

खदान खुलने से स्थानीय युवाओं को रोजगार, ग्रामीणों के कारोबार को मिल सकती है गति; परिवहन, व्यापार, सड़क और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं

सूरजपुर प्रतापपुर। विकासखंड प्रतापपुर के ग्राम मदननगर में प्रस्तावित कोयला खदान को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं। खदान परियोजना को लेकर ग्रामीणों के बीच जहां कुछ लोग जमीन, मुआवजे और विस्थापन को लेकर चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं के रोजगार और क्षेत्र के विकास को लेकर नई उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। माना जा रहा है कि यदि खदान परियोजना शुरू होती है और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार तथा व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसका लाभ मदननगर सहित आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है।

रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने की मजबूरी हो सकती है कम- प्रतापपुर क्षेत्र के अनेक युवा रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों और राज्यों का रुख करते हैं। ऐसे में मदननगर में प्रस्तावित कोयला खदान स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर बन सकती है। खनन कार्यों के अलावा मशीन ऑपरेटर, वाहन चालक, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, सुरक्षा कर्मचारी, तकनीकी सहायक और अन्य कार्यों में रोजगार की संभावनाएं बन सकती हैं। यदि स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर भर्ती में प्राथमिकता दी जाती है, तो उन्हें अपने क्षेत्र में ही आजीविका का साधन मिल सकता है।

छोटे व्यापारियों और ग्रामीणों को भी मिल सकता है लाभ- खदान शुरू होने से केवल नौकरीपेशा लोगों को ही नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों और ग्रामीण व्यवसायियों को भी लाभ मिलने की संभावना है। खदान में काम करने वाले कर्मचारियों और वाहनों की आवाजाही बढ़ने से चाय-नाश्ता, होटल, किराना दुकान, मोटर गैरेज, स्पेयर पार्ट्स और अन्य दुकानों की मांग बढ़ सकती है। वहीं स्थानीय किसानों को दूध, सब्जी, अनाज और अन्य खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए नया बाजार मिल सकता है। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

परिवहन और वाहन व्यवसाय में खुल सकते हैं अवसर- कोयला



खदान से जुड़े परिवहन कार्यों में ट्रक, पिकअप और अन्य मालवाहक वाहनों की आवश्यकता हो सकती है। इससे स्थानीय वाहन मालिकों, चालकों और वाहन मरम्मत से जुड़े लोगों को काम मिलने की संभावना है। इसके अलावा लोडिंग, अनलोडिंग, मशीनरी रखरखाव और अन्य सहायक कार्यों में भी रोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं। स्थानीय युवाओं को इन कार्यों में प्रशिक्षण और प्राथमिकता मिले तो क्षेत्र में स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है।

सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद- बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के साथ क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास की संभावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। परियोजना से संबंधित स्वीकृत कार्यों और सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के अवसर बन सकते हैं।

युवाओं के भविष्य को लेकर संवाद की जरूरत- मदननगर में प्रस्तावित खदान को लेकर समर्थन और विरोध के बीच अब सबसे ज्यादा जरूरत आपसी संवाद की है। स्थानीय युवाओं को परियोजना से मिलने वाले संभावित रोजगार, प्रशिक्षण और व्यवसाय के अवसरों की जानकारी हासिल करनी चाहिए। वहीं ग्रामीणों की मांगों और प्रभावित परिवारों के अधिकारों को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। प्रशासन, खदान प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच सकारात्मक चर्चा से ऐसा रास्ता निकल सकता है, जिसमें विकास के साथ स्थानीय लोगों के हित भी सुरक्षित रहें। क्षेत्र के युवाओं को उम्मीद है कि मदननगर की प्रस्तावित खदान रोजगार और आर्थिक उन्नति का नया माध्यम बन सकती है। अब जरूरत इस बात की है कि इन संभावनाओं को केवल दावों तक सीमित न रखकर स्थानीय रोजगार, उचित मुआवजे, पुनर्वास और विकास की ठोस कार्ययोजना में बदला जाए, ताकि मदननगर सहित आसपास के गांवों का भविष्य बेहतर बनाया जा सके।

छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली में स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ भवन शासकीय कर्मचारी विभागीय समिति, नई दिल्ली द्वारा आज स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री मनीष ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।



कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर पूजा-अर्चना एवं छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के सामूहिक गायन के साथ हुआ।

इस अवसर पर विशेष अतिथि श्री मनीष ठाकुर ने संगठन की मजबूती एवं हितों की रक्षा के लिए एकजुटता को आवश्यक बताते हुए सभी सदस्यों से आपसी समन्वय, सहयोग एवं संगठनात्मक एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन की वास्तविक शक्ति उसकी एकता और सामूहिक प्रयासों में निहित होती है।

कार्यक्रम में श्री समय सिंह, कोषाध्यक्ष तथा ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर्स कन्फेडरेशन के वरिष्ठ सदस्य श्री राधेश्याम ने भी अपने अनुभव साझा किए तथा संगठन को मजबूत बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए।

समारोह के दौरान समिति का निर्वाचन भी संपन्न हुआ। उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पूर्व पदाधिकारियों पर पुनः विश्वास व्यक्त करते हुए श्री कन्हैया कुमार को अध्यक्ष, श्री नंदन सिंह गोसाई को सचिव तथा श्री नंद कुमार गोंड़ को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया।

नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समिति के उद्देश्यों की पूर्ति, संगठन की एकता तथा कर्मचारी हितों के संरक्षण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम का समापन आपसी सौहार्द, संगठनात्मक एकता एवं भविष्य में मिलकर कार्य करने के संकल्प के साथ हुआ।

पटवारियों की मांगों के समर्थन में उतरा कांग्रेस विधि विभाग, सरकार से शीघ्र समाधान की मांग

वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार झा बोले- पटवारियों की समस्याओं का निराकरण कर उपलब्ध कराएं आवश्यक सुविधाएं



ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उठाई जा रही आवाज को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग ने समर्थन दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रदेश महासचिव एवं बस्तर संभाग प्रभारी वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार से पटवारियों की जायज मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है।

अवधेश कुमार झा ने कहा कि राजस्व विभाग शासन-प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई है। पटवारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आम जनता और शासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। भूमि अभिलेखों का संधारण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, गिरदावरी, फसल संबंधी जानकारी और प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षति का आकलन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके द्वारा निभाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व व्यवस्था को सुचारु एवं पारदर्शी बनाए रखने में पटवारियों की भूमिका अहम है। ऐसे में उनके कार्यभार, जिम्मेदारियों और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

झा ने कहा कि लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखना प्रत्येक कर्मचारी संगठन का अधिकार है। सरकार को टकराव की स्थिति पैदा होने से पहले संगठन के प्रतिनिधियों से सकारात्मक संवाद स्थापित करना चाहिए।

उन्होंने राज्य सरकार से पटवारियों को कार्य के अनुरूप आवश्यक संसाधन, सुविधाएं और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही कहा कि कांग्रेस विधि विभाग पटवारी संघ की न्यायोचित मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़ा है।

बाढ़ प्रभावित बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आए बड़ेमुरमा के विद्यार्थी, 8 हजार रुपये की जुटाई सहायता राशि

जूनियर रेडक्रॉस सोसायटी की पहल से 300 से अधिक बच्चों को मिली पाठ्य सामग्री, जिला शिक्षा अधिकारी ने साक्षी कश्यप को किया सम्मानित

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ

जगदलपुर। बस्तर जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ेमुरमा की जूनियर रेडक्रॉस सोसायटी के विद्यार्थियों ने मानवीय पहल की है। विद्यार्थियों ने स्वयं 8 हजार रुपये एकत्रित कर बाढ़ प्रभावित गांवों के 300 से अधिक जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की। इस सेवा कार्य के लिए जिला शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल ने छात्रा साक्षी कश्यप को सम्मानित किया।



सहायक नोडल अधिकारी मनीष अहीर के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की टीम ने बकावंड विकासखंड के कोहकापाल, लिटिगुड़ा, कुरुषपाल एवं मालगांव में लगभग 300 बच्चों को कॉपी, पेन और पेंसिल की स्टेशनरी किट वितरित की। वहीं बस्तर विकासखंड के ग्राम कुड़कानार में 30 बच्चों को स्टेशनरी किट के साथ बिस्किट भी प्रदान किए गए।

इस सेवा कार्य में विद्यालय के प्राचार्य जीवन दास सहित कांता प्रसाद वैद्य, समीर नाग, डीके देवांगन, राजेंद्र धुर्वे, पुनीत राम फरदिया, मोहित, राजेश गुप्ता, तुलादास मानिकपुरी, नीलमणि साहू, जितेंद्र साहू, राजेश्वरी, गुड़िया, सरोज, अंजली एवं नीलीमा सहित अन्य सदस्यों का सहयोग रहा। जिला जूनियर रेडक्रॉस नोडल अधिकारी एलेक्स जेंडर का भी मार्गदर्शन मिला। विद्यार्थियों की इस पहल ने आपदा के समय जरूरतमंदों की सहायता, शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया।

कंदीय फसलों की उन्नत खेती से किसानों को मिलेगा बेहतर मुनाफा, 30 से अधिक कृषकों ने लिया प्रशिक्षण

प्रक्षेत्र भ्रमण के दौरान वैज्ञानिकों ने बताई आधुनिक उत्पादन तकनीकें, कृषि सामग्री का भी किया वितरण

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ

जगदलपुर, । किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और कंदीय फसलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र कुम्हरावण्ड, जगदलपुर में एक दिवसीय प्रक्षेत्र भ्रमण सह-कृषक प्रशिक्षण एवं कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखिल भारतीय समन्वित कंद फसल अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत शनिवार 31 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यक्रम में तोकापाल विकासखंड के ग्राम पोटानार से आए 30 से अधिक किसानों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्र के सह-संचालक अनुसंधान डॉ. एके ठाकुर ने किसानों को कंदीय फसलों की खेती के आर्थिक एवं पोषण संबंधी लाभों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को पारंपरिक खेती के साथ कंदीय फसलों को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

परियोजना प्रभारी डॉ. पद्माक्षी ठाकुर ने किसानों को अनुसंधान प्रक्षेत्र का भ्रमण कराते हुए विभिन्न कंदीय फसलों की उन्नत किस्मों, आधुनिक उत्पादन तकनीकों एवं वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी दी। वहीं डॉ. गुंजा ठाकुर ने कंदीय फसलों के उचित भंडारण और लघु वर्गीय कंद फसलों के उत्पादन की तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया।

प्रशिक्षण के समापन पर किसानों को उन्नत सब्जी बीज, कीटनाशक, मुनगा एवं अमरूद के पौधे तथा फसल सुरक्षा और उपज सुखाने के लिए तिरपाल वितरित किए गए। इस पहल से किसानों को वैज्ञानिक खेती की नई तकनीकों को समझने और अपनाने का अवसर मिला।

परफॉरमेंस गारंटी की सड़क के क्षतिग्रस्त मिलने तथा खराब गुणवत्ता पर ठेकेदार और अधिकारियों को नोटिस जारी

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर ग्राम बानौ से कान्हाभैरा मार्ग की हुई जांच

पीडब्लूडी ने की कार्रवाई, सड़कों की गुणवत्ता और अच्छे रखरखाव पर विभाग का जोर

कवर्धा , उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर ग्राम बानौ से कान्हाभैरा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत मिलने पर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, बोड़ला उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा विगत 27 अक्टूबर को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 6.70 किलोमीटर लंबे मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पूरी चौड़ाई में तथा कुछ स्थानों पर सड़क के बाई ओर का हिस्सा धंसना पाया गया। जांच में सड़क की गुणवत्ता में कमी एवं क्षति सामने आने पर लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई करते हुए संबंधित ठेकेदार और अभियंताओं को नोटिस जारी किया है। क्षतिग्रस्त हिस्सों को उखाड़कर जीएसबी सतह से निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुधार करने की आवश्यकता है। उक्त सड़क परफॉर्मेंस गारंटी अवधि के अंतर्गत है। लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार मेसर्स कन्हैया लाल अग्रवाल को सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को सात दिनों के भीतर सुधार कर इनके फेटोग्राफ्स कार्यपालन अभियंता को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में सुधार कार्य नहीं करने पर अनुबंध के अनुसार ठेकेदार के रिस्क एण्ड कास्ट पर सुधार कराकर रोकी गई परफॉर्मेन्स गारंटी की राशि से भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए ठेकेदार खुद जिम्मेदार होगा। उल्लेखनीय है कि ठेकेदार मेसर्स कन्हैया लाल अग्रवाल द्वारा 6.70 किमी लंबे ग्राम बानौ से कान्हाभैरा मार्ग (पुल-पुलियों सहित) का निर्माण इस साल फरवरी में पूर्ण किया गया था। यह सड़क फरवरी-2031 तक पांच वर्षों की परफॉरमेंस गारंटी में है।



तत्कालीन एसडीओ और उप अभियंता को भी नोटिस, कम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

लोक निर्माण विभाग ने विभागीय अधिकारियों द्वारा सड़क के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की अवधि में मार्ग का पर्याप्त कम्पेक्शन नहीं पाए जाने पर इसे कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी उमाप्रसाद जोशी और उप अभियंता एल.आर. छत्तरे को नोटिस जारी किया है। विभाग ने दोनों अधिकारियों को कम्पेक्शन टेस्ट की विस्तृत रिपोर्ट कार्यपालन अभियंता को तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए आरोप पत्र जारी कर विभागीय जाँच प्रस्तावित की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली में डॉ.मनीषा त्रिपाठी ने स्थापित किया कीर्तिमान

जनता के गोठ विश्व हिंदी परिषद अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन दो दिवसीय (दि.30-31 अक्टूबर 2026) विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित शोध संगोष्ठी /शोध (आलेख)वाचन 139 प्रतिभागियों में से चयनित 21 श्रेष्ठ आलेख में से रायगढ़ (छत्तीसगढ़)से एकमात्र सर्वश्रेष्ठ आलेख हेतु डॉ.मनीषा त्रिपाठी (राज्यपाल से पुरस्कृत), संयोजक विश्व हिंदी परिषद रायगढ़ ने स्थापित किया कीर्तिमान सम्मेलन में उपस्थित अतिविशिष्ट अतिथियों में डॉ.श्रवण कुमार, केंद्रीय समन्वयक विश्व हिंदी परिषद एवं सदस्य पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, डॉ.विपिन कुमार राष्ट्रीय महासचिव, विश्व हिंदी परिषद, विदेश एवं वित मंत्रालय भारत सरकार, श्री विनोद बंसल राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिन्दू परिषद, प्रोफेसर महासिंह पूनिया अध्यक्ष, हिंदी विभाग एवं निदेशक लोक-संपर्क विभाग कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, सुश्री अथिला कोतवाल संस्थापक - निदेशक हिन्दी संस्थान श्रीलंका, स्वामी विवेकानंद केंद्र कोलंबो,श्री संजय पासवान बिहार विधान परिषद, सदस्य एवं पूर्व मंत्री भारत सरकार ने की मुक्त कंठ से की प्रशंसा, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा सभागार सम्मान समारोह में मंचासीन रहे माननीय जुएल उरांव जी केन्द्रिय जनजातीय मामले भारत सरकार, डॉ.अशोक कुमार भार्गव आईएएस. डॉ.पी.के.पुरोहित प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, के हाथों डॉ.मनीषा त्रिपाठी को प्रशस्ति-पत्र सह मोमेंटो से सम्मानित किया गया। डॉ.मनीषा त्रिपाठी के आलेख के बारे में पुनः प्रशंसा मंचसीन अतिथियों ने की,साथ ही उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर होने की शुभकामनाएं दी। इस स्वर्णिम उपलब्धि हेतु इष्ट मित्रों, स्नेहीजनों, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन, कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन आदि ने बधाईयां प्रेषित की।



सियार के हमले से युवक घायल, ग्रामीणों ने पकड़कर किया पिंजरे में कैद, लगातार बढ़ रही जानवरों के शिकार का मामला





कवर्धा: कबीरधाम जिले में वन्य प्राणियों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। पिछले दिनों लोहारा वन परिक्षेत्र में तेंदुए के हमले से एक ग्रामीण के घायल होने के बाद अब छपरी गांव में सियार के हमले की घटना सामने आई है। देर शाम बाइक से जा रहे ग्रामीण पर सियार ने हमला कर दिया, जिससे उसके हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने सियार को पकड़कर जाली में बंद कर दिया। वहीं, शहर में तेंदुए की मौजूदगी से पहले ही लोगों में दहशत बनी हुई है।

कबीरधाम जिले के छपरी गांव में देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बाइक से गुजर रहे एक ग्रामीण पर सियार ने अचानक हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण के हाथों में गहरी चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सियार को पकड़कर जाली में बंद कर दिया। इस घटना ने गांव में वन्य प्राणियों की मौजूदगी और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

वहीं, दूसरी घटना लोहारा वन परिक्षेत्र के कुटकीपारा गांव के पास जंगल की है। यहां लकड़ी काटने गए ग्रामीण तेकराम ध्रुव पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। हमले में उसके हाथ और कंधे पर चोटें आईं। घायल को तत्काल लोहारा उपस्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल ग्रामीण की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

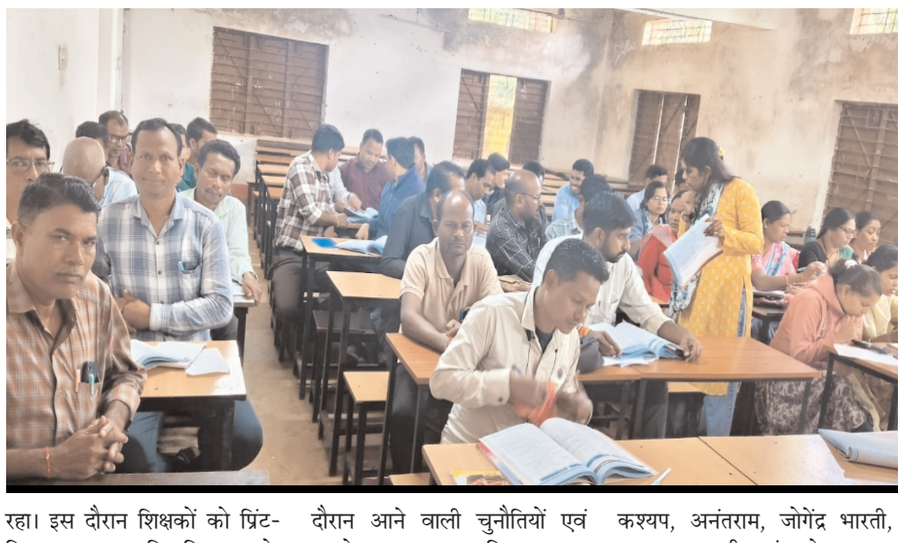
इधर, कवर्धा शहर के भीतर तेंदुए का वीडियो सामने आने के बाद से ही शहरवासियों में दहशत का माहौल है। जिले के अलग-अलग इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी की सूचनाएं मिल रही हैं। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए जाल और पिंजरे के साथ बकरी को चारे के रूप में रखकर रेस्क्यू की तैयारी की गई है, लेकिन अब तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने कबीरधाम जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में वन्य प्राणियों की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब वन विभाग के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दूसरी ओर वन्य प्राणियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके प्राकृतिक आवास तक पहुंचाना।

बकावंड के 240 स्कूलों में बुनियादी शिक्षा मजबूत करने पर जोर, 7 जोन में हुई अकादमिक समीक्षा बैठक

एफएलएन/एमएलई कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को दिया गया मार्गदर्शन, भाषा एवं गणित की दक्षताओं को बेहतर बनाने पर हुई चर्चा

ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ

जगदलपुर। बस्तर जिले के विकासखंड बकावंड में एफएलएन/एमएलई कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शनिवार को 7 जोन में जोन स्तरीय मासिक अकादमिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें विकासखंड के 240 चयनित विद्यालयों के शिक्षकों ने सहभागिता की। बैठक विकासखंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर यादव एवं खंड स्रोत समन्वयक सोन सिंग बघेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) को मजबूत करना तथा बच्चों की भाषा और गणित संबंधी दक्षताओं में सुधार लाना रहा। इस दौरान शिक्षकों को प्रिंट-रिच वातावरण विकसित करने, पठन-लेखन कोना तैयार करने, उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने, स्थानीय भाषा से अकादमिक भाषा की ओर बच्चों को आगे बढ़ाने, वर्ण पहचान एवं डिकोडिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही गणित की 9 मुख्य दक्षताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शिक्षकों ने विद्यालयों में शिक्षण के दौरान आने वाली चुनौतियों एवं अपने अनुभव साझा किए। कक्षा-कक्ष में गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति अपनाने और बच्चों की नियमित शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में बीआरजी सदस्य महेंद्र कुमार पांडे, मोहित पांडे, ऋतु राजवाड़े, चूड़ामणि कंवर, प्रदीप जोशी, डोमेंद्र गंगबेर, एस.एन. सिदार, नेऊर लाल कश्यप, अनंतराम, जोगेंद्र भारती, रामकृष्णा ढाली एवं भुनेश कुमार नेताम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं एलएलएफ टीम से ईश्वर साहू एवं विपिन पानीग्राही भी उपस्थित रहे। बैठक के माध्यम से शिक्षकों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और एफएलएन/एमएलई कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर साझा समझ विकसित करने का प्रयास किया गया।



संपादकीय

जनप्रतिनिधित्व कानून

इस समय मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर का मुद्दा चर्चा में है। निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1950) की धारा 21 तथा निर्वाचक-पंजीकरण-नियम (1960) के नियम 25(1) के माध्यम से यह अधिकार प्राप्त है। आयोग तीन प्रकार से पुनरीक्षण कर सकता है। सामान्य पुनरीक्षण, विशेष पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण जिसमें मतदाता सूची से मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित आदि मतदाताओं के नाम हटाए और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। चूंकि विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची एकदम नए सिरे से बनाई जाती है, इसीलिए इसमें ज्यादा समस्याएं आती हैं। जमीनी स्तर पर बीएलओ आदि कर्मचारियों से त्रुटियां होती हैं, पर उसे वोट चोरी का नाम देना गलत है। मगर कुछ दलों ने राजनीतिक लाभ हेतु वोट चोरी का नैरेटिव चला रखा है।

चुनाव आयोग वर्ष में चार बार-एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर-को 18 वर्षीय नागरिकों का मतदाता के रूप में पंजीकरण करता है। यहां तक कि यदि कोई नागरिक 17 वर्ष का है, तो भी वह अपना पंजीकरण करा सकता है, ताकि 18 वर्ष की आयु होने पर उसका नाम मतदाता सूची में स्वत: जुड़ जाए। अत: युवाओं को किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। फिर भी, यदि किसी का नाम मतदाता सूची से कट गया है, तो वह फार्म-6 भर कर अपना नाम अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से जुड़वा सकता है। यदि चुनाव शुरू हो भी जाएं तब भी प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। जहां एक ओर चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट करने तथा महिलाओं, 85 वर्ष के मतदाताओं, दिव्यांगों और अन्य वैध-मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का अथक प्रयास करता है, वहीं कुछ लोग मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद इसलिए मतदान नहीं कर पाते, क्योंकि उनका नाम मतदाता-सूची से कट जाता है। कभी-कभी तो पूरा परिवार ही मतदाता सूची से गायब हो जाता है, जबकि उन सभी के पास मतदाता पहचान पत्र होता है। चुनाव आयोग 12 अन्य पहचान पत्रों को मान्यता देता है, जिससे मतदाता अपना नाम सूची में होने पर उन्हें दिखा कर मतदान कर सकता है। तब प्रश्न उठता है कि मतदाता पहचान पत्र का फिर क्या औचित्य? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) को 1958 में संशोधित कर मतदाता पहचान पत्र को कानूनी-वैधता प्रदान की गई। चुनाव आयोग का मतदाता पहचान पत्र विशेष होता है, उस पर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो मतदाता सूची में मतदाता के नाम पर भी अंकित होता है। अन्य किसी पहचान पत्र में वह नंबर नहीं होता। अत: आयोग के अधिकारी 'चेक' कर सकते हैं कि किसी मतदाता पहचान पत्र के अल्फा न्यूमेरिक नंबर का क्या हुआ? क्यों वह हटाया गया? क्या वह कहीं और चला गया या किसी दूसरी जगह उसका मतदाता पहचान पत्र बना है? जिन मतदाताओं के नाम गलती से सूची से कट गए, वे अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करें? क्या उनका तत्काल पंजीकरण कर मतदान सुनिश्चित नहीं किया जा सकता?

मुट्ठी भर अमीरों की कीमत चुका रही हैं पूरी दुनिया

- ललित गर्ग



दुनिया आज एक ऐसे विरोधाभास के दौर से गुजर रही है, जहां एक ओर विकास, समृद्धि और आधुनिकता के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबी, भुखमरी, हिंसा, विस्थापन और पर्यावरणीय विनाश की चुनौतियां लगातार विकराल होती जा रही हैं। प्रश्न यह है कि जब दुनिया के पास पर्याप्त संसाधन हैं, विज्ञान और तकनीक ने अभूतपूर्व प्रगति की है, तब भी करोड़ों लोग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम की रिपोर्ट 'डिजास्टर डिवाइड' इसी प्रश्न का एक असहज, किंतु विचारोत्तेजक उत्तर प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि जलवायु संकट केवल प्रकृति की नाराजगी नहीं, बल्कि आर्थिक असमानता, अनियंत्रित उपभोग और संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों के बढ़ते नियंत्रण का परिणाम भी है। दुनिया की लगभग 80 लाख आबादी वाले सबसे धनी 0.1 प्रतिशत वर्ग की जीवनशैली और निवेश से होने वाला कार्बन उत्सर्जन करोड़ों नहीं, अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, यह वर्ग दुनिया के सबसे गरीब 44 प्रतिशत लोगों की तुलना में अधिक कार्बन प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। यह असमानता केवल आंकड़ों का अंतर नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनहीनता का ऐसा दस्तावेज है, जिसमें कुछ लोगों की विलासिता की कीमत पूरी मानवता चुका रही है। निजी विमान, विशाल नौकाएं, अत्यधिक ऊर्जा खपत और प्रदूषणकारी उद्योगों में निवेश आधुनिक अमीरी के प्रतीक बन गए हैं, जबकि दूसरी ओर गरीब आबादी स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। सवाल यह नहीं कि किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, बल्कि यह है कि उसकी संपन्नता का सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य कौन चुका रहा है। इस संकट का सबसे भयावह पक्ष यह है कि जलवायु आपदाएं भी अमीर और गरीब के बीच भेदभाव करने लगी हैं। बाढ़ एक ही समय में अमीर की आलीशान कोठी और गरीब की झोपड़ी तक पहुंचती है, लेकिन दोनों के परिणाम अलग होते हैं। अमीर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं, बीमा और आधुनिक सुविधाओं से नुकसान की भरपाई कर लेते हैं, जबकि गरीब अपना घर, खेत, पशुधन और आजीविका गंवाकर वर्षों पीछे चला जाता है। ऑक्सफैम के अनुसार, अधिक आर्थिक असमानता वाले देशों में बाढ़ से होने वाली मौतें सात गुना तक अधिक होती हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों का उत्सर्जन भविष्य में लगभग 19 लाख अतिरिक्त गर्मी-संबंधी मौतों का कारण बन सकता है। इनमें 78 प्रतिशत मौतें निम्न एवं निम्न-मध्यम आय वाले देशों में होने का अनुमान है। आर्थिक असमानता का यह अंतर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। जब समाज में संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का वितरण अन्यायपूर्ण हो जाता है, तब असंतोष जन्म लेता है। बेरोजगारी, महंगाई, खाद्य संकट, जल संकट और विस्थापन सामाजिक तनाव को बढ़ाते हैं। धीरे-धीरे यही तनाव आक्रोश, विद्रोह, अपराध, सामुदायिक संघर्ष और हिंसा का रूप ले सकता है। यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रत्येक हिंसा के पीछे केवल अमीरी-गरीबी का अंतर है, लेकिन जब विकास का लाभ सीमित हाथों में सिमटता है और संकट का बोझ बहुसंख्यक आबादी पर पड़ता है, तब सामाजिक शांति की नींव कमजोर होना स्वाभाविक है। विडंबना यह है कि कुछ बड़े निवेशक पहले प्रदूषणकारी उद्योगों से मुनाफा कमाते हैं और फिर उन्हीं आपदाओं से निपटने, सफाई तथा पुनर्निर्माण के कारोबार में लाभ अर्जित करते हैं। ऑक्सफैम का 'डिस्ट्रॉय एंड रीबिल्ड इंडेक्स' 217 कंपनियों के माध्यम से इसी दोहरे मुनाफे की पड़ताल करता है। यह सचमुच ऐसी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है, जहां किसी के लिए आपदा भी अवसर बन जाती है और किसी के लिए जीवनभर का अभिशाप।

भारत के संदर्भ में यह चेतावनी और भी गंभीर है। भारत की विशाल आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि, निर्माण, छोटे व्यवसायों और असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है। किसान अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और तापमान वृद्धि से जूझ रहा है। मजदूर भीषण गर्मी में काम करने को विवश है और महानगरों की झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले परिवार जलभराव तथा गर्मी की दोहरी मार झेल रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार, भारत की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी ऐसे जिलों में रहती है जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं के जोखिम में हैं। वहीं, देश के 57 प्रतिशत जिलों में रहने वाली लगभग 76 प्रतिशत आबादी अत्यधिक गर्मी के उच्च या बहुत उच्च जोखिम का सामना कर रही है।

कांग्रेस का नया नारा -आइडिया आफ इंडिया

- राकेश अचल



नयी दिल्ली के रामलीला मैदान मे 1 नवंबर को होने वाली रैली का स्वरुप अचानक बदल गया है.अब इस रैली का ध्येय वाक्य 'आइडिया ऑफ इंडिया' है.1 नवंबर की रैली को राहुल गांधी ने फ्री फॉर ऑल कर दिया है। यानी जो चाहे, इस रैली में शामिल हो सकता है.लेकिन सवाल यह है कि क्या रामलीला मैदान की यह रैली भारतीय राजनीति में कोई नया इतिहास रचने जा रही है? क्या यह रैली विपक्ष की एकजुटता का नया अध्याय लिखेगी? क्या यह रैली सत्ता के सामने कोई नई चुनौती पेश कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रैली मौसम की मार, सरकार के दबाव और पुलिस की तमाम बंदिशों को झेल पाएगी?

इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। रामलीला मैदान भारतीय राजनीति का कोई साधारण मैदान नहीं है। इस मैदान ने कई आंदोलन देखे हैं, कई सरकारों को चुनौती देते हुए देखा है और कई बार सत्ता के अहंकार को जनता की ताकत के सामने झुकते हुए भी देखा है।

लेकिन हर रैली इतिहास नहीं बनती। इतिहास तब बनता है, जब भीड़ किसी राजनीतिक दल के समर्थन में नहीं, बल्कि किसी बड़े विचार और उद्देश्य के लिए सड़कों पर उतरती है।

इस बार नारा है— आइडिया ऑफ इंडिया !यह नारा अपने आप में बहुत व्यापक है। इसका मतलब है ऐसा भारत, जिसमें लोकतंत्र हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, असहमति का सम्मान हो, सभी नागरिकों को बराबरी मिले और सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह हो।लेकिन क्या विपक्ष इस विचार को लेकर जनता के बीच कोई ठोस संदेश दे पाएगा?

राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे इस रैली को केवल कांग्रेस या विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन बनाकर न छोड़ दें। अगर इस मंच से उठने वाली आवाज देश के आम नागरिक की आवाज बनती है, तभी इसका राजनीतिक महत्व बढ़ेगा। दूसरी तरफ, भाजपा और केंद्र सरकार भी इस रैली को सामान्य घटना मानकर नहीं चल सकतीं। विपक्ष की एक बड़ी रैली का महत्व केवल उसमें जुटने वाली भीड़ से नहीं, बल्कि उसके बाद बनने वाले राजनीतिक माहौल से तय होता है।लेकिन यहाँ एक और सवाल है।क्या विपक्षी दल अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक साझा राजनीतिक उद्देश्य पर टिक पाएँगे? क्या वे जनता के सामने केवल विरोध का नहीं, बल्कि विकल्प का भी कार्यक्रम रखेंगे?क्योंकि सरकार का विरोध करना एक बात है और जनता के सामने एक विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करना दूसरी बात। और अब बात मौसम, सरकार और पुलिस की। क्या रैली के दिन मौसम साथ देगा? क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएँ पर्याप्त होंगी? क्या पुलिस और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल रैली की दिशा तय करेंगे? इन सवालों का जवाब समय ही देगा। लेकिन लोकतंत्र में शांतिपूर्ण सभा और विरोध का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल की कृपा पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

आखिरकार, असली परीक्षा रामलीला मैदान में जुटने वाली भीड़ की नहीं, उस भीड़ से निकलने वाले संदेश की होगी।

अगर यह रैली केवल भाषणों, नारों और नेताओं की तस्वीरों तक सीमित रह गई, तो अगले दिन इसकी चर्चा भी खत्म हो सकती है।लेकिन अगर इस रैली से संविधान, लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और जनता के सवालों पर कोई व्यापक जनसंवाद शुरू होता है, तो इसका असर रामलीला मैदान से बाहर भी दिखाई दे सकता है।और तब सवाल भाजपा के विजय रथ का ही नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की दिशा का भी होगा।

1 नवंबर की रैली क्या सचमुच कोई नया इतिहास रचेगी? क्या 'आइडिया ऑफ इंडिया' केवल एक नारा रहेगा या कोई व्यापक राजनीतिक आंदोलन बनेगा?इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें रैली के भाषणों से आगे जाकर उसके संदेश, उसकी एकजुटता और उसके बाद की राजनीतिक कार्रवाई पर भी नजर रखनी होगी।

स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर

श्रीपद येस्सो नाइक

जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते तापमान, बदलते मौसम और ऊर्जा असुरक्षा के दोहरे संकट से जूझ रही है, तब भारत ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का एक ऐसा रास्ता चुना है, जो आने वाले दशकों में उसकी आर्थिक और रणनीतिक ताकत की बुनियाद बन सकता है। पिछले 12 वर्षों में देश का ऊर्जा परिदृश्य जिस तेजी से बदला है, वह सिर्फ बिजली उत्पादन के आंकड़ों में बढ़ोतरी की कहानी नहीं है। यह आत्मनिर्भरता का एक नया सोपान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर ऊर्जा परिवर्तन की शुरुआत की है। सौर और पवन ऊर्जा का तेज विस्तार, रूफटाप सोलर, पीएम-कुसुम, पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना, बड़े सोलर पार्क, आफशोर विंड प्रोजेक्ट, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन- ये सभी एक ऐसी व्यापक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका लक्ष्य केवल कार्बन उत्सर्जन घटाना नहीं, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर चुकी है। सौर और पवन ऊर्जा इसके सबसे बड़े आधार हैं और कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। भारत को अंदाजा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल देश में बिजली की मांग में और तेज वृद्धि होना तय है। हालांकि भारत की ऊर्जा नीति केवल नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर रहने की नीति नहीं है। देश को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली की जरूरत है। यहां आकर थर्मल पावर और परमाणु ऊर्जा का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन भारत की रणनीति पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा को एक-दूसरे के विकल्प के रूप में देखने के बजाय एक संतुलित ऊर्जा मिश्रण तैयार करने की है। कोयला और परमाणु ऊर्जा से स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, दूसरी तरफ सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। यह दृष्टिकोण भारत के ऊर्जा परिवर्तन को व्यावहारिक बनाता है। क्योंकि केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। चुनौती यह भी है कि जब सूरज नहीं निकले या हवा की गति कम हो, तब भी घरों, अस्पतालों, उद्योगों, रेलवे, परिवहन और तेजी से बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली मिलती रहे। इसी वजह से बैटरी एनर्जी स्टोरेज, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन जैसी तकनीकों पर जोर बढ़ रहा है। सोलर पंप किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने के साथ डीजल पर निर्भरता घटाते हैं। वहीं अनुपयोगी या कम उपयोग वाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाने वाले किसान अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय का नया स्रोत तैयार कर सकते हैं। ऊर्जा परिवर्तन किसाना को 'ऊर्जादाता' बनने का भी अवसर दे रहा है। यह बदलाव सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है। शहरों में रूफटाप सोलर ने मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बिजली की लागत कम करने का रास्ता खोला है। पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के जरिए घरों की छतों को छोटे ऊर्जा केंद्रों में बदलने की दिशा में काम हो रहा है।

आज का राशिफल

मेष राशि: आज आपको वाद-विवाद से दूर रहना होगा। आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा।

वृष राशि: विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में अभी और मेहनत करने की जरूरत है।

मिथुन राशि: आज आप किसी काम को करने के नए तरीके पर विचार करेंगे इससे काम समय से व आसानी से पूरा हो जाएगा।

कर्क राशि: आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। आपकी सूझबूझ और विवेक से समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी।

सिंह राशि: आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपकी निजी समस्या सुलझ जाने से मानसिक शांति मिलेगी।

कन्या राशि: आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कार्यवाही में सफलता मिलेगी।

तुला राशि: दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।

वृश्चिक राशि: आज व्यावसायिक संपर्कों को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आज कारोबार में आपको फायदा होगा।

धनु राशि: आज आपके व्यवहार में विनम्रता और लचीलापन ही आपको सफलता दिला सकता है।

मकर राशि: आज अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और काम के प्रति एकाग्र चित्त होना आपको सफलता देगा।

कुंभ राशि: आज आपको किसी विशेष आयोजन में जाने का मौका मिलेगा और नई जानकारियां सीखने को मिलेगी।

मीन राशि: आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज परिवार संबंधी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह-मशवरा होगा।

व्यंग्य - हार का झटका, नागपुर-वाराणसी पे अटका!

(संजय एम तराणेकर)

चुनाव में हार-जीत तो लगी रहती है, लेकिन जब जीत का घोड़ा दौड़ते-दौड़ते अचानक ठोकर खा जाए तो सवार को भी अपनी सवारी पर शक होने लगता है। चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों में सत्तापक्ष को मिले झटकों ने कुछ ऐसा ही माहौल बना दिया है। खासकर नागपुर में विपक्ष की जीत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यानी एक ही तीर वह भी बड़ा गंभीर। जैसे सत्ता पक्ष के दिल पर चोट कर दी हो।

नागपुर कोई साधारण जगह नहीं है। इसे संघ का मुख्यालय होने का गौरव प्राप्त है। ऐसे में वहां विपक्ष की जीत होना सत्तापक्ष के लिए किसी राजनीतिक पहेली से कम नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब घर के आसपास ही मतदाताओं का मिजाज बदलने लगे तो चुनावी रणनीतिकार आखिर किस दिशा में रणनीति बना रहे हैं?

प्रधानमंत्री ने विपक्ष की सीटों को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसा, लेकिन प्रकृति का न्याय देखिए कि कुछ ही समय बाद नागपुर ने ऐसा जवाब दिया कि राजनीतिक व्यंग्य का विषय ही बदल गया। लगता है मतदाता भी अब सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़कर नहीं, अपनी पसंद से वोट डालने लगे हैं। इससे यह भी साबित होता है कि सोशल मीडिया पर जल्दबाजी में पोस्ट करना कितना भारी पड़ सकता है। इधर झट से पोस्ट की और उधर नुकसान हो गया।

उधर वाराणसी में भी सायकलवालों की जीत ने सत्तापक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब इसे विपक्ष की किस्मत कहें या मतदाताओं की नाराजगी, लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है।

वैसे चुनाव हारने के बाद आत्ममंथन करने की परंपरा बड़ी दिलचस्प है। हर पार्टी आत्ममंथन का ऐलान करती है, बैठकें होती हैं, रिपोर्ट बनती है और फिर अगले चुनाव में वही पुराने चेहरे, वही पुराने वादे और वही पुराने भाषण मैदान में उतर आते हैं। वैसे ही जैसे आते-जाते लहरों की तरह।

सच तो यह है कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी स्थायी विजेता नहीं होती। कुर्सी का तकिया कितना भी मुलायम क्यों न हो, जनता जब करवट बदलती है तो सत्तापक्ष की नींद उड़ ही जाती है। इसलिए बेहतर है कि नेता जनता की आवाज सुनें, वरना ईवीएम से पहले मतदाता ही राजनीतिक नींद का अलार्म बजा देते हैं!

जोखिम बढ़ाता बढ़ता व्यापार घाटा

- डॉ. जयंतीलाल भंडारी



हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे की चुनौती का सामना कर रहा है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2015-16 के 52.5 अरब डालर से दोगुने से अधिक होकर 2025-26 में 112 अरब डालर हो गया। हालांकि चीन को भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन वहां से आयात की बड़ी मात्रा व्यापार घाटे को और बढ़ा रही है।

चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक असंतुलन के पीछे कई संरचनात्मक और नीतिगत कारक जिम्मेदार हैं। इसका प्रमुख कारण चीन की गैर-शुल्क बाधाएं हैं। वित्त मंत्री के अनुसार, चीनी प्रशासन के जटिल तकनीकी, स्वास्थ्य और गुणवत्ता मानक भारतीय वस्तुओं के चीनी बाजार में प्रवेश को बाधित करते हैं। भारत एक दशक से अधिक समय से अपनी जेनेरिक दवाओं, प्रसंस्कृत मांस और कृषि उत्पादों के लिए चीनी बाजार में उचित पहुंच की मांग करता रहा है। जबकि चीन घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए जटिल नियम लागू करता है। इसके चलते भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धी कीमतों और गुणवत्ता के बावजूद चीनी बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाते। इसके अलावा चीनी युआन की विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ता है।

चीन के साथ व्यापारिक असंतुलन का एक अन्य पहलू 'मेक इन इंडिया' अभियान के बावजूद चीनी कच्चे माल और घटकों पर भारत की निर्भरता है। हालांकि भारत का घरेलू विनिर्माण क्षेत्र हाल के वर्षों में बढ़ा है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन अब भी चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है। भारत का इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, डिस्प्ले पैनल, सोलर पीवी सेल, औषधीय कच्चा माल यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रीडिएंट्स (एपीआइ) और भारी औद्योगिक मशीनरी के लिए चीन से आयात पर निर्भरता बनी हुई है। इस निर्भरता के कारण भारत में औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण बढ़ने के साथ चीनी कलपुर्जों का आयात भी बढ़ता है। साथ ही चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों, लीथियम और आधुनिक उर्वरकों के उत्पादन एवं निर्यात पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। ये संसाधन भारत के इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं। इनकी सीमित आपूर्ति और ऊंची कीमतों के कारण भारत को हर साल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।

चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए केवल जवाबी सीमा शुल्क लगाना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। इसके बजाय भारत को व्यापक रणनीति अपनानी होगी। इसकी पहली प्राथमिकता इलेक्ट्रानिक्स और सेमीकंडक्टर का घरेलू इकोसिस्टम विकसित करना होना चाहिए। भारत को अंतिम उत्पादों की असेंबलिंग के बजाय घटक स्तर पर निर्माण बढ़ाना होगा। जब तक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एडवांस्ड सेंसर, डिस्प्ले पैनल और सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन देश में शुरू नहीं होता, तब तक चीन पर निर्भरता समाप्त नहीं होगी। दूसरा कदम फार्मास्यूटिकल्स और बल्क ड्रग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन उसका दवा उद्योग एपीआइ के लिए 70 प्रतिशत तक चीन पर निर्भर है। यह निर्भरता रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा करती है।

इस निर्भरता को कम करने के लिए देश में घोषित बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना तेज करनी होगी और 41 महत्वपूर्ण एपीआइ के घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू करनी होंगी। साथ ही चीन की गैर-शुल्क बाधाओं का मुकाबला करने के लिए भारत को कूटनीतिक प्रयासों के साथ देश में क्वालिटी कंट्रोल आर्डर लागू करने होंगे। अमानक चीनी सामान की डंपिंग रोकने के लिए गुणवत्ता मानक तय करना जरूरी है, ताकि घरेलू विनिर्माताओं को प्रतिस्पर्धा का उचित माहौल मिल सके। भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और 'फ्रेंड-शोरिंग' की नीति अपनानी होगी। क्रिटिकल मिनरल्स, दुर्लभ धातुओं और उच्च तकनीकी उत्पादों के लिए चीन पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से समान विचारधारा वाले देशों के साथ वैकल्पिक आपूर्ति नेटवर्क तैयार करना होगा। ग्रीन टेक्नोलाजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार के दौर में यदि भारत ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा नहीं दिया तो जीवाश्म ईंधन के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम होने के बाद चीन से हरित प्रौद्योगिकी के आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है।

चीन से बढ़ता व्यापार घाटा केवल आयात-निर्यात का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्थिरता, औद्योगिक क्षमता और रणनीतिक संप्रभुता से जुड़ा विषय है। इसीलिए हमें घरेलू वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता बनाना होगा। हमें चीन को आर्थिक प्रतिस्पर्धी मानते हुए उससे मुकाबले के प्रयास करने होंगे। उद्योग और कारोबार में शोध एवं नवाचार के लिए संसाधन बढ़ाने होंगे। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन, गुणवत्ता मानकों के पालन तथा व्यापारिक साझेदारों के विविधीकरण के प्रयासों को गति देनी होगी। इन प्रयासों से भारत चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता और व्यापार घाटे को चरणबद्ध ढंग से कम कर वैश्विक व्यापार में एक संतुलित और आत्मनिर्भर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा।

बैगा अंचल में 61 परिवारों की सनातन धर्म में वापसी, विधायक भावना बोहरा ने पखारे पैर

महिडबरा में संस्कृति गौरव अभिनंदन समारोह का आयोजन, शॉल और श्रीफल भेंटकर परिवारों का किया सम्मान





कवर्धा। कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड के बैगा बाहुल्य वनांचल क्षेत्र महिडबरा में संस्कृति गौरव अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। जनजाति एवं वनांचल क्षेत्र सर्व समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पंडरिया विधायक भावना बोहरा शामिल हुई। समारोह के दौरान आयोजकों ने बैगा आदिवासी, यादव समाज सहित विभिन्न समाजों के 61 परिवारों की सनातन धर्म में पुनः वापसी का दावा किया। इस अवसर पर विधायक भावना बोहरा ने पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार परिवारों के सदस्यों के पैर पखारे और शॉल एवं श्रीफल भेंटकर उनका अभिनंदन किया।

विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पूर्व में वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा की कमी का फायदा उठाकर भोले-भाले ग्रामीणों को आर्थिक सहायता और अन्य प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था। अब समाज के लोगों के साथ मिलकर ऐसे परिवारों को उनकी मूल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी संस्कृति, परंपरा, पुरखों की विरासत और ग्राम देवी-देवताओं के प्रति आस्था से जुड़ी है। भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों ने जनजातीय अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना प्रत्येक समाज की जिम्मेदारी है।

भावना बोहरा ने कहा कि वह इस आयोजन में विधायक के रूप में नहीं, बल्कि समाजसेविका के तौर पर शामिल हुई हैं। समाज और संस्कृति के संरक्षण के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विरोधियों की ओर से बदनाम करने की कोशिशों के बावजूद वह अपने अभियान से पीछे नहीं हटेंगी।

गौरतलब है कि विधायक इससे पहले भी 600 से अधिक परिवारों की सनातन धर्म में वापसी कराने का दावा कर चुकी हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जनजातीय समाज के प्रमुख, सामाजिक प्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे।

30-40 वर्षों की सेवाओं को मिला सम्मान, 16 सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी हुए सम्मानित

कलेक्टर आकाश छिकारा ने शॉल, श्रीफल और पेंशन प्राधिकार पत्र देकर किया सम्मान, बोले- समाज को आज भी उनके अनुभव की जरूरत



ओमप्रकाश रजक/जनता के गोठ

जगदलपुर, । जिला कलेक्टोरेट के आस्था कक्ष में सोमवार को अक्टूबर माह में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए 16 अधिकारी-कर्मचारियों के सम्मान में गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर आकाश छिकारा ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शॉल, श्रीफल एवं पेंशन प्राधिकार पत्र भेंटकर सम्मानित किया तथा उनके स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की कामना की।

इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि जीवन के 30 से 40 वर्ष पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ शासकीय सेवा में देना गौरवपूर्ण उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर के विकास में सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। इसे जीवन की दूसरी पारी समझकर परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत रुचियों को समय दें। साथ ही अपने अनुभव और ज्ञान से युवाओं एवं समाज को मार्गदर्शन देते रहें।

कलेक्टर ने जिला कोषालय की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए बताया कि जिले में लगभग 80 से 90 प्रतिशत मामलों में सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ एवं अन्य पेंशन संबंधी लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने अपने 39 वर्षों के सेवाकाल के अनुभव साझा किए तथा शिक्षा के क्षेत्र में आए सकारात्मक बदलावों का उल्लेख किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ तन्मय खन्ना, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अनिल कुमार पाठक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों के परिजन उपस्थित रहे।

जिले की 485 राशन दुकानों में दूसरे दिन भी लटका ताला, हजारों हितग्राही परेशान

नौ सूत्रीय मांगों को लेकर राशन विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान



भुजबल बघेल

बकावंड जनता के गोठ। बस्तर जिले में राशन विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिले की सभी 485 राशन दुकानें दूसरे दिन भी बंद रहीं। दुकानों में ताला लटका होने के कारण हजारों राशन कार्डधारी हितग्राहियों को सरकारी खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नौ सूत्रीय मांगों को लेकर बस्तर राशन विक्रेता संघ ने अपना आंदोलन जारी रखा है। संघ के सदस्यों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इसी के चलते उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

राशन विक्रेताओं की प्रमुख मांगों में मानदेय में वृद्धि, कमीशन बढ़ाने और उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने सहित नौ सूत्रीय मांगें शामिल हैं। संघ का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद विक्रेताओं को पर्याप्त मानदेय और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इधर, जिले की सभी 485 राशन दुकानों के बंद रहने से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेष रूप से वे हितग्राही प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी खाद्यान्न संबंधी जरूरतें सरकारी राशन पर निर्भर हैं।

अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन राशन विक्रेताओं की मांगों के समाधान के लिए कब पहल करता है और हितग्राहियों को नियमित राशन वितरण की सुविधा कब बहाल हो पाती है। फिलहाल राशन विक्रेता संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी नौ सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होतीं, तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।

स्कूल परिवार ने स्नेहा चंद्रा को किया सम्मानित



कमल खुंटे/जनता के गोठ

बिर्रा। डीडीएस स्कूल बिर्रा की कक्षा आठवीं की छात्रा स्नेहा चंद्रा ने विद्यालय, विकासखण्ड और जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा कार्यालय द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में स्नेहा चंद्रा ने भाग लेकर शानदार प्रदर्शन किया। जिसके लिए उन्हें 3 अक्टूबर 2026 को पी एम श्री सेजेस क्र. 01 जांजगीर में प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर डीडीएस स्कूल बिर्रा परिवार ने प्रार्थना सभा में स्नेहा का प्रमाण-पत्र व शील्ड के साथ सम्मान किया और उसके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं व शुभचिंतक स्नेहीजन उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ को सुशासन में आदर्श और अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाना हमारा संकल्प: राज्यपाल रमेन डेका



जनता के गोठ- रायपुर नवा रायपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने गठन के 26 गौरवशाली वर्षों की यात्रा पूरी कर ली है और अब प्रदेश नई जिम्मेदारियों, असीम संभावनाओं तथा दृढ़ संकल्पों के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। नवा रायपुर में आयोजित 'छत्तीसगढ़ राज्योत्सव-2026' के द्वितीय दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को सुशासन में आदर्श, अर्थव्यवस्था में सशक्त और सामाजिक समरसता में अग्रणी राज्य बनाना हमारा साझा संकल्प है। उन्होंने विश्वास जताया कि युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और जनजातीय समाज के सामूहिक प्रयासों से छत्तीसगढ़ 'विकसित भारत' के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और सभी पुरखों के योगदान को नमन किया।

बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास का नया सवेरा राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति की पहली शर्त शांति और सुरक्षा है। बस्तर अंचल में शांति स्थापना की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। कभी हिंसा से प्रभावित रहे दूरस्थ इलाकों में अब सड़क, बिजली, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ स्कूल खुल रहे हैं और आजीविका मिशन के जरिए रोजगार-स्वरोजगार सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों के अदम्य साहस को नमन किया और मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि सकारात्मक बदलाव को स्थायी बनाने के लिए सुरक्षा के साथ आजीविका का विस्तार आवश्यक है।

अबूझमाड़ में 'शैक्षिक नगर' और नवा रायपुर में 'एआई डाटा सेंटर'-युवाओं और आधुनिक तकनीक पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में 'शैक्षिक नगर' विकसित करने की पहल राज्य के स्वर्णिम भविष्य की नींव रखेगी। वहीं, नवा रायपुर में प्रस्तावित सेमीकंडक्टर इकाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित डाटा सेंटर पार्क जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगी। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना, स्टार्टअप्स और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों के समन्वय से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को उद्यमी बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। राज्यपाल ने रेखांकित किया कि प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन नहीं, बल्कि सतत विकास ही भविष्य की सुरक्षा है। उन्होंने विशेष

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर



कमल खुंटे/जनता के गोठ

बिर्रा। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत जैजैपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मल्दा के तत्वाधान में शुक्ला हॉस्पिटल बिर्रा के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम मल्दा सहित आसपास के गांवों के लगभग 60-62 ग्रामीणों ने लाभ उठाया। शिविर में मुख्य रूप से स्त्री रोग एवं मेडिसिन विभाग के तहत निःशुल्क खून जांच, बीपी-शुगर जांच एवं निःशुल्क दवा वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉ. शुभम शुक्ला, डॉ. विजय हांडे, डॉ. आकृति शुक्ला, डॉ. प्रकाश कुमार, श्रवण कुमार, रामावतार, सोम केंवट, भोला कश्यप, राकेश पटेल, पल्लवी तिवारी, सुनील यादव, ललित केंवट, माधव पटेल सहित सरपंच शशि लाला मित्तल एवं वार्ड सदस्यों ने सेवाएं प्रदान की। डॉ. शुभम शुक्ला ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर बेहतर जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है, साथ ही आयोजन के लिए सरपंच शशि लाला मित्तल का आभार व्यक्त किया।

जेठ ने छोटे भाई की पत्नी की पटक-पटककर की हत्या, गांव में मचा हड़कंप

मोहगांव में सनसनीखेज वारदात, आरोपी देव सिंह निषाद पुलिस हिरासत में; हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं





कवर्धा। कबीरधाम जिले के लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहगांव में रिश्तों को कलंकित करने वाली हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी की कथित तौर पर पटक-पटककर हत्या कर दी। घटना में मृतका की पहचान हेमलता निषाद के रूप में हुई है, जबकि आरोपी की पहचान देव सिंह निषाद के रूप में की गई है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात की खबर फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी देव सिंह निषाद ने अपने छोटे भाई की पत्नी हेमलता निषाद पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लोहारा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

हालांकि, इस जघन्य वारदात के पीछे की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। प्रारंभिक तौर पर पारिवारिक विवाद सहित अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पुलिस मृतका और आरोपी के बीच संबंधों, घटना से पहले हुए विवाद तथा वारदात की परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है। घटना के बाद मोहगांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर अपराध दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच और पूछताछ के बाद ही हत्या के वास्तविक कारणों तथा वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

एनएमडीसी भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल

बस्तर के युवाओं को मिले रोजगार में प्राथमिकता : सांसद महेश कश्यप

बस्तर के संसाधनों से देश का विकास हो रहा है,स्थानीय युवाओं की रोजगार में सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक : विधायक चैतराम अटामी



जगदलपुर जनता के गोठ। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी की एल-1 एवं एल-2 भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने तथा उन्हें रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय युवाओं के हितों,भर्ती प्रक्रिया में उनकी सहभागिता तथा रोजगार के अवसरों से जुड़े विषयों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया।

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर के युवाओं को उनके ही क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है द्य एनएमडीसी की एल-1 एवं एल-2 भर्ती सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए,ताकि उन्हें अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो सके। इस विषय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। हमें उम्मीद है कि स्थानीय युवाओं के हित में सकारात्मक पहल होगी।

दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि दंतेवाड़ा सहित संपूर्ण बस्तर के युवाओं में प्रतिभा और कार्यक्षमता की कोई कमी नहीं है। जिस क्षेत्र के संसाधनों से देश के विकास को गति मिल रही है,उस क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के माध्यम से विकास की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है। एनएमडीसी की एल-1 एवं एल-2 भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्हें न्यायसंगत अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हमारा निरंतर प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित हो।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि एनएमडीसी की भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक पहल की जाए, जिससे बस्तर के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें और क्षेत्र के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। इस अवसर पर दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी,उपाध्यक्ष अरविन्द कुंजाम,जिला पंचायत सदस्य सोमरू कड़ती,करण तामो,राजू कड़ती,रवि नाग,सुनील मंडावी,ईश्वर कुमार,सुनील मड़ावी,सुरेश कश्यप सहित अन्य युवा साथी एवं प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उपस्थित रहे।

खबर-खास

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनूठी पहल, मेले में ही मिलेगा निजी बोरवेल और कुओं के पानी की जांच का निःशुल्क अवसर

जनता के गोठ- रायपुर- रायपुर, 02 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर आयोजित राज्योत्सव 2026 (01 से 03 नवंबर 2026) में इस बार आम नागरिकों के स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल को लेकर एक विशेष सुविधा शुरू की गई है। मेले में आने वाले नागरिकों को अपनी निजी जल स्रोतों की शुद्धता परखने का सीधा मौका मिल रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्योत्सव के इस तीन दिवसीय भव्य आयोजन के दौरान विभागीय प्रदर्शनी स्थल पर पेयजल का प्रत्यक्ष रासायनिक जल परीक्षण किया जा रहा है। नागरिक अपने पीने और सिंचाई के पानी की गुणवत्ता (जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी धातुएं और बैक्टीरिया) की जांच बिना किसी शुल्क के सरकारी प्रयोगशालाओं में करवा सकते हैं।

निःशुल्क जल परीक्षण का लाभ उठाएं- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दी जा रही इस सुविधा के तहत यदि कोई भी हितग्राही अपने घर के निजी ट्यूबवेल (बोरवेल) या कुएं के पानी की गुणवत्ता की जांच कराना चाहता है, तो वह बेहद आसानी से इसका लाभ उठा सकता है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य प्रदर्शनी स्थल, राज्योत्सव परिसर में संपर्क किया जा सकता है। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। जल नमूनों की जांच के तुरंत बाद विभागीय काउंटर से ही परीक्षण रिपोर्ट भी प्रदान की जा रही है, जिससे नागरिकों को पानी में मौजूद तत्वों और उसकी पीने योग्य स्थिति की सटीक जानकारी मिल सके।

शुद्ध पेयजल के प्रति जागरूकता पर जोर- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इस स्टॉल पर विशेषज्ञों द्वारा आगंतुकों को पानी की गुणवत्ता, भू-जल संरक्षण और सुरक्षित पेयजल के उपायों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। राज्योत्सव में शामिल होने वाले आमजन इस विशेष सेवा का लाभ उठाकर अपने परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। प्रशासन ने अपील की है कि अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने जल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच करवाएं।

वरिष्ठ नेता स्व. डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को मंत्री राजेश अग्रवाल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि



जनता के गोठ- रायपुर - बालोद/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सोमवार को प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता स्व. डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के पैतृक ग्राम भेंडरा (जिला बालोद) पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री श्री अग्रवाल ने स्व. कोर्सेवाड़ा के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति- श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि स्व. डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के लिए एक बड़ी एवं अपूरणीय क्षति है। उनका संपूर्ण जीवन सादगी, निष्ठा और जनसेवा को समर्पित रहा। अपने सरल, सहज और मिलनसार स्वभाव की बदौलत उन्होंने समाज के हर वर्ग के दिलों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी।

जनहित को सदैव रखा सर्वोपरि- मंत्री श्री अग्रवाल ने उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि स्व. कोर्सेवाड़ा ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता दी। आम जनता से उनका गहरा और आत्मीय जुड़ाव था। समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति उनकी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सार्वजनिक जीवन में निःस्वार्थ सेवा की एक अनुपम मिसाल है।

दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ- शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि किसी प्रियजन का बिछड़ना पूरे परिवार के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। इस कठिन समय में हम सभी परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

खेल-खेल में शिक्षा, नवाचार से बच्चों का भविष्य संवार रहे प्रधान पाठक खगेश रात्रे; बिलासपुर में मिला राज्यस्तरीय सम्मान

पलारी के प्रधान पाठक ने शिक्षण के साथ सामाजिक सरोकारों में भी बनाई अलग पहचान

जनता के गोठ/ओंकार साहू
बलौदाबाजार। शिक्षक की पहचान सिर्फकिताबों से पढ़ाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने के प्रयासों से बनती है। इसी सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सामाजिक जागरूकता की अलख जगा रहे विकासखंड पलारी के प्रधान पाठक खगेश कुमार रात्रे को शिक्षक प्रतिभा अकादमी छत्तीसगढ़ ने शिक्षक प्रतिभा सम्मान-2026 से सम्मानित किया है। 31 अक्टूबर को बिलासपुर के पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में उन्हें स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। शासकीय प्राथमिक शाला गबौद (ल), संकुल केंद्र सोनारदेवरी में पदस्थ खगेश रात्रे



बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखते। वे खेल-खेल में शिक्षा, रचनात्मक गतिविधियों और नए शिक्षण प्रयोगों के जरिए पढ़ाई को रोचक और आनंददायक बना रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, बालिका शिक्षा तथा शाला छोड़ चुके और स्कूल से दूर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सम्मान के पीछे छिपी है सेवा और समर्पण की कहानी। खगेश रात्रे ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने विद्यालय परिवार और सहयोगियों को देते हुए आयोजक समिति के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में और बेहतर शैक्षणिक नवाचार करने तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की प्रेरणा देगा। शिक्षक प्रतिभा अकादमी के संयोजक भरत कुमार, अध्यक्ष सुमित पाण्डेय सहित आयोजन समिति के सदस्यों के सहयोग से समारोह संपन्न हुआ। खगेश रात्रे की यह उपलब्धि पलारी क्षेत्र के शिक्षा जगत के लिए गौरव की बात है।

मटनार करपावंड मूली प्रधानमंत्री सड़क बदहाल, जगह-जगह बने बड़े गड्ढे

सड़क की गिट्टी उखड़ने से राहगीर और बाइक सवार परेशान, मरम्मत की ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं



भुजबल बघेल 7 बकावंड जनता के गोठ विकासखंड बकावंड ब्लॉक के अंतर्गतअंतर्गत मटनार से करपावंड होते हुए मूली जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क इन दिनों बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं और कई स्थानों पर सड़क की गिट्टी उखड़कर बिखर गई है। इसके चलते राहगीरों, साइकिल चालकों और दोपहिया वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है। गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खासकर बाइक सवारों और पैदल चलने वाले लोगों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क की स्थिति और भी खराब हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मरम्मत कराने के लिए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से मटनारङ्करपावंडङ्कमूली मार्ग का निरीक्षण कर जल्द से जल्द मरम्मत कार्य कराने की मांग की है, ताकि क्षेत्रवासियों को आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिल सके।

तक्षशिला कंप्यूटर सेंटर में प्रतिभाओं का सम्मान, हुनरमंद विद्यार्थियों को मिला मंच

जनता के गोठ/ओंकार साहू
बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को तक्षशिला कंप्यूटर सेंटर सिमगा में छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान राखी निर्माण, मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सेंटर संचालक दीपक साहू ने कहा कि शिक्षा के साथ रचनात्मकता, नवाचार और व्यावहारिक कौशल का ज्ञान भी जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (हश्वक्क) भी कौशल आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। मुख्य अतिथि पारस पाटकर ने विद्यार्थियों को मेहनत और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। विशिष्ट अतिथि चंद्रप्रकाश टोडे ने दीपक साहू के शैक्षणिक प्रयासों की सराहना की, वहीं सतनामी समाज परिक्षेत्र अध्यक्ष शत्रुघन मार्कण्डेय ने युवाओं को छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी बनने का संदेश दिया। कार्यक्रम में नए विद्यार्थियों को बैग एवं पुराने छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया गया। छात्र-छात्राओं ने राजकीय गीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मंत्री टंकराम वर्मा के जिला पंचायत रायपुर प्रतिनिधि गिरीश साहू की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, राम कोसले, सदानंद साहू, हिमांशु देवांगन, तारणी साहू सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंटकर आभार व्यक्त किया गया।



धान खरीदी की तैयारी में जुटी प्रशासन, 145 केंद्रों पर होगा खरीद, दो एकड़ वाले किसान एक मुस्त बेच सकेंगे धान

37 नए उपार्जन केंद्र खुले, 48 नई सहकारी समितियों का गठन; अवैध धान परिवहन रोकने छह सीमावर्ती क्षेत्रों में बनेंगे चेक पोस्ट



कवर्धा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। इसे लेकर कबीरधाम जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस वर्ष जिले में 37 नए धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं, जिसके बाद खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। वहीं किसानों की सुविधा के लिए 48 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। खाद्य विभाग का दावा है कि 10 नवंबर तक सभी खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी।

जिले में इस बार एक लाख 10 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की जाएगी। किसानों को टोकन के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत दो एकड़ तक भूमि वाले किसानों को एक टोकन मिलेगा, जबकि पांच से दस एकड़ तक भूमि वाले किसानों को दो टोकन दिए जाएंगे। किसान संबंधित मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

धान खरीदी के दौरान बारदानों की कमी न हो, इसके लिए भी विभाग ने तैयारी की है। इस बार पीडीएस और मिलर्स से मिलने वाले पुराने बारदानों के साथ मार्कफेड द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नए बारदानों का इस्तेमाल किया जाएगा।

दूसरी ओर, दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खपाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था मजबूत की है। जिले के छह सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। यहां तहसीलदार, खाद्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें वाहनों की जांच करेंगी। अवैध भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए दिन-रात गश्त भी की जाएगी।

अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के साथ अवैध धान परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने की होगी। किसानों को टोकन, बारदाना और खरीदी केंद्रों पर कितनी बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, इसका पता खरीदी शुरू होने के बाद चलेगा।

भाजपा ने निकाली लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ भव्य पदयात्रा



भुजबल बघेल जगदलपुर बकावंड जनता के गोठ। भारतीय जनता पार्टी ने आज सोमवार को लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ भव्य पदयात्रा संभाग मुख्यालय जगदलपुर में निकाली। बरसते पानी के बीच हज़ारों की संख्या में लोग भाजपा की पदयात्रा में शामिल हुये। भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा का नेतृत्व केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। पदयात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप प्रमुखता से शामिल हुये।

कांग्रेस व विपक्षी दलों सहित स्वार्थी अराजक तत्वों के खिलाफ भाजपा ने लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा का आयोजन किया था। मांई दंतेश्वरी मंदिर के सामने भाजपा के नेताओं ने पहले विशाल जनसभा को संबोधित किया। जिसके बाद हज़ारों हज़ार लोगों के साथ भाजपा की भव्य पदयात्रा शहर में निकाली गयी। बिगड़े मौसम व बार बार बरसते बादलों के बीच जिले भर से हजारों कार्यकर्ता और नागरिक भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा में उत्साह के साथ सम्मिलित हुये। पैलैस रोड, संजय मार्केट चौक, जिला महारानी अस्पताल रोड, चांदनी चौक, स्टेट बैंक चौक, मेन रोड, गोलबाजार,सिरहासार चौक से होकर भाजपा की भव्य पदयात्रा मांई दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष पुन: पहुंच कर संपन्न हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं व नागरिकों के प्रति आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। पदयात्रा में प्रमुख रूप से सांसद महेश कश्यप, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश लाटिया, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, जिपं अध्यक्ष वेदवती कश्यप, महापौर संजय पाण्डेय, विद्याशरण तिवारी, योगेन्द्र पाण्डेय, श्रीनिवास मिश्रा, सुधीर पाण्डेय, शिवनारायण पाण्डेय, रामाश्रय सिंह, बलदेव मण्डावी, आर्येंद्र सिंह आर्य, खेमसिंह देवांगन, रजनीश पाणिग्रही,परीस बेसरा, नरसिंह राव, ललिता बघेल,सफीरा साहू, रामकुमारी यादव, फूलसिंह सेठिया, नारायण ठाकुर,खीतेश मौर्य,किरण सेन, रोहित त्रिवेदी, प्रकाश झा, अविनाश श्रीवास्तव, महेन्द्र सेठिया, तरुण पाण्डेय, पुरूषोत्तम जोशी, हरिराम मण्डावी, देवीप्रसाद बेंजाम,सुनील कुर्रामी, मंगतू कश्यप, सोमारू राम कश्यप, सुखदेव मण्डावी, प्रवीण सांखला, माहेश्वरी ठाकुर, अभिलाष यादव,नीलाम्बर सेठिया, योगेश ठाकुर,विनय सोना, अज़ीज़ खान आदि सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व नागरिक शामिल रहे।

जनता के द्वार पहुंचेगी सरकार: धरसींवा में 21 नवंबर से विधायक अनुज शर्मा निकालेंगे 'सेवा संवाद यात्रा'

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

खरोरा (धरसींवा)। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा, सुशासन और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प के साथ विधायक अनुज शर्मा आगामी 21 नवंबर से 'सेवा संवाद यात्रा' शुरू करने जा रहे हैं। एक महीने तक अनवरत चलने वाले इस महाअभियान की रूपरेखा तय करने के लिए धरसींवा स्थित 'सेवा सदन' में भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और मंडल कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक संपन्न हुई।

धरसींवा मेरा परिवार, जनता की सेवा ही सर्वोच्च प्राथमिकता: अनुज शर्मा- बैठक को संबोधित करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि धरसींवा विधानसभा उनका परिवार है और क्षेत्र के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना उनका प्राथमिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा, यह 'सेवा संवाद यात्रा' महज कोई राजनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता के बीच पहुंचकर उनके सुख-दुख साझा करने और उम्मीदों को धरातल पर साकार करने का महाअभियान है। केंद्र और राज्य की 'डबल इंजन' सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना हमारा मुख्य लक्ष्य है।

सभी 144 गांवों का दौरा, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान- इस एक माह की यात्रा के दौरान विधायक अनुज शर्मा अपनी टीम के साथ क्षेत्र के सभी 144 गांवों, नगर पंचायत के वार्डों और हर एक मतदान केंद्र (बूथ) तक पहुंचेंगे। यात्रा की सबसे प्रमुख विशेषता यह होगी कि आमजन की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए मौके पर ही विशेष 'समस्या निवारण शिविर' लगाए जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी और नए विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण भी संपन्न होगा।



मातृशक्ति और युवाओं के हाथ कमान, कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प

अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने मातृशक्ति और युवा मोर्चा को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने और घर-घर तक विकास का संदेश पहुंचाने का संकल्प दोहराया।

1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर निकली छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान रैली , छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता का दिया संदेश

अंचल वर्मा - दुर्ग, उतई। जनता के गोठ।

दुर्ग :- डुण्डेरा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान रैली एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की माटी, भाषा, संस्कृति, परंपरा और छत्तीसगढ़िया अस्मिता के सम्मान का संदेश दिया गया। आयोजन के तहत कचरू नगर, डुण्डेरा से छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान रैली निकाली गई। रैली में छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के पदाधिकारियों, सेनानियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने सहभागिता की। रैली के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने तथा छत्तीसगढ़िया समाज में एकता, स्वाभिमान और जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया। रैली के



पश्चात डुंडेरा में आयोजित सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकपरंपराओं, लोककला और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। नवागांव, उतई स्थित छत्तीसगढ़ी लोककला मंच, बेरा में आयोजित मंचीय कार्यक्रम में लोकसंस्कृति के संरक्षण और नई पीढ़ी तक छत्तीसगढ़ की परंपराओं को पहुँचाने के महत्व को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के महापुरुषों, पुरखों और राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के योगदान को स्मरण करना तथा प्रदेश की भाषा, संस्कृति, जल-जंगल-जमीन और समाज के हक-अधिकारों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना रहा। आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी माटी, किसान, मजदूर, आदिवासी समाज, लोककलाकारों और मेहनतकश जनता की गौरवशाली परंपराओं में निहित है। आयोजकों ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को मजबूत करने का भी दिन है। प्रदेश की भाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना अउ जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी ,जिला पदाधिकारी, खड़ गुड़ी,पार,सम्मानित सेनानी /ग्रामवासियों सभी के सहयोग और सहभागिता से यह आयोजन छत्तीसगढ़िया एकता, सांस्कृतिक गौरव और स्वाभिमान का संदेश देने में सफल रहा। इस कार्यक्रम में नल कुमार साहू , मोहन लाल साहू , हर्षित चंद्राकर सुमंत क्षत्रिय, संजय साहू , दीपक चंदेल , ज्ञानेंद्र , नील कुमार साहू , आर्यन राजपत , केशव साहू , हेमकुमार साहू ,परमानद साहू और सभी कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण जन की उपस्थिति रही।



साउथ एक्सेंट पर ट्रोलिंग को लेकर बोलीं ईशा देओल

अभिनेत्री ईशा देओल 15 साल बाद एक्शन-क्राइम ड्रामा फिल्म 'प्रताप' से बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में साउथ इंडियन एक्टर्स के एक्सेंट को लेकर ट्रोल किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री का कहना है कि उन्हें साउथ इंडियन एक्सेंट काफी 'प्यारा' और 'क्यूट' लगता है।
ईशा ने कहा, 'जब मैं अपने डायलॉग बोलती हूं, खासकर हिंदी में, तो मैं काफी हद तक अपनी मां जैसी लगती हूं, लेकिन असल में मैं वैसी ही हूं और जिन्होंने मुझे किसी खास किरदार के लिए लिया है, वो ये बात अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि साउथ इंडियन लोगों का हल्का-सा एक्सेंट सुनना बहुत प्यारा और क्यूट लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है।'
अभिनेत्री ने आगे बताया कि बॉलीवुड में भी ऐसी कई दिग्गज अभिनेत्रियां हैं, जिनकी बोली में साउथ इंडियन एक्सेंट सुनने को मिलता है। उन्होंने कहा, 'और भी कुछ लोगों जैसे श्री आंटी, मेरी मम्मी और उर्मिला में भी साउथ इंडियन एक्सेंट सुनने को मिलता है। उर्मिला की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूं और उनकी बोली में जो हल्का-सा एक्सेंट आता है, वो मुझे पसंद है।'
अभिनेत्री ने आगे कहा कि लोगों के बोलने के तरीके का मजाक उड़ाने के बजाय भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की सराहना करना जरूरी है। दरअसल, साउथ इंडियन एक्सेंट को लेकर चर्चा तब तेज हो गई जब अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' में अपने साउथ इंडियन एक्सेंट को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर खुलकर बात की थी।
इस एपिसोड में रश्मिका अपने पति और अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ नजर आई थीं। शो के दौरान रश्मिका ने कहा कि वे दक्षिण भारत से हैं, इसलिए उनके बोलने के लहजे में वहां की झलक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। रश्मिका ने यह भी बताया कि वे अपनी फिल्मों के लिए खुद अलग-अलग भाषाओं में डबिंग करने में गर्व महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रोलिंग उन्हें अपना काम करने से नहीं रोक सकती।



पहली बार पंकज त्रिपाठी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी अदिति राव हैदर

अभिनेत्री अदिति राव हैदरी आगामी पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पारिवारिक मनोरंजन' में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ नजर आएंगी। अभिनेत्री ने बताया कि को-स्टार पंकज त्रिपाठी के साथ काम करना उनके मजेदार अनुभवों में से एक रहा। अभिनेत्री का कहना है कि पंकज त्रिपाठी का सहज ह्यूमर सीन को हल्का और मजेदार बनाने में मदद करता है। अदिति राव हैदरी ने कहा, 'पंकज जी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करना सच में बहुत खुशी की बात थी। उनका ह्यूमर इतना सहज और नेचुरल है कि हर सीन हल्का और ज्यादा मजेदार लगने लगा।' अभिनेत्री इस फिल्म में 'हेलेन' नाम का किरदार निभा रही हैं, जो एक प्रॉपर्टी मैनेजर और हाउसकीपर के रूप में रंजन के घर आती हैं। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने कहा, 'यह एक ऐसी फिल्म है, जिसमें हमारे दर्शकों को रोमांस, ह्यूमर और फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। यह एक ऐसी फिल्म है, जिसे हमारे दर्शक चाहने वालों के साथ देखना पसंद करेंगे। मुझे इस किरदार के साथ काम करने में बहुत मजा आया है। उसकी खूबियों को और वो अपने आसपास के लोगों से कैसे जुड़ती है, ये सब खोजने में।'
वहीं, पंकज त्रिपाठी ने फिल्म को लेकर कहा, 'मुझे इस फिल्म में इसकी सादगी, किरदारों का असल जिंदगी से जुड़ा होना और ह्यूमर के छोटे-छोटे पल बहुत पसंद आए, जो फैमिली स्टोरीज को खास बनाते हैं। इसमें परिवार की गर्मजोशी है, थोड़ा रोमांस है और वो मजा है जो इसे त्योहारों में देखने के लिए परफेक्ट बनाता है। इस फिल्म का हिस्सा बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि दर्शक भी अपने चाहने वालों के साथ इस फिल्म को एन्जॉय करें।'
यह फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसमें रोमांस, ह्यूमर और फैमिली ड्रामा का तड़का है। फिल्म का मकसद त्योहारों के मौके पर दर्शकों को एक हल्की-फुल्की फिल्म देना है, जिसे वे अपने परिवार के साथ एन्जॉय कर सकें। 'पारिवारिक मनोरंजन' अदिति और पंकज की साथ में पहली फिल्म है, जो 13 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज होगी।





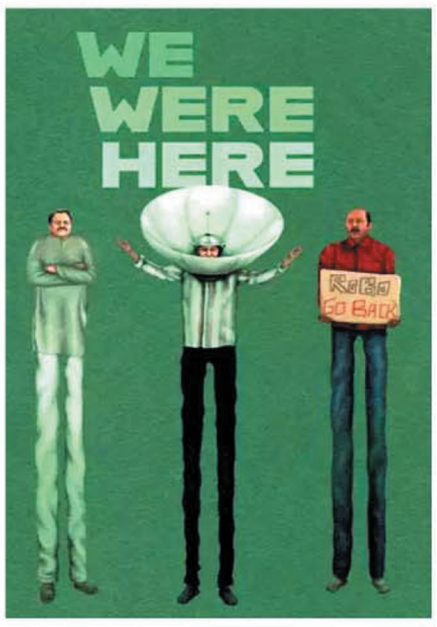
आईपीएस नित्या रेड्डी बन न्याय के लिए उठाएंगी आवाज़ साई पल्लवी

ओम: चैप्टर 1' को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच फिल्म के निर्माताओं ने साई पल्लवी के किरदार आईपीएस नित्या रेड्डी का नया टीजर जारी कर दिया है। टीजर में साई पल्लवी एक बिल्कुल नए और दमदार अवतार में नजर आ रही हैं, जो धनुष और ममूटी अभिनीत इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में एक नया रोमांच जोड़ता है। अपनी शानदार अदाकारी और सहज पर्दे पर मौजूदगी के लिए मशहूर साई पल्लवी इस बार खाकी वर्दी में नजर आएंगी। 'ओम: चैप्टर 1' के नए टीजर में उनके किरदार की झलक देखने को मिलती है, लेकिन कहानी में उनकी भूमिका क्या मोड़ लेकर आएगी, इसे लेकर निर्माताओं ने फिलहाल रहस्य बरकरार रखा है। साई पल्लवी के अभिनय सफर में यह किरदार एक दिलचस्प नया पड़ाव माना जा रहा है। अपने पिछले किरदारों से अलग, इस बार वह एक पुलिस अधिकारी के रूप में न्याय के लिए खड़ी नजर आएंगी। भारतीय सिनेमा के कुछ बेहतरीन कलाकारों से सजी इस फिल्म में उनकी एंट्री ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।
फिल्म में साई पल्लवी की भूमिका को लेकर आरटेक स्टूडियोज की निर्माता श्रद्धा अग्रवाल ने कहा, 'साई पल्लवी एक शानदार अभिनेत्री हैं और हम हमेशा से उनकी अदाकारी में नजर आने वाली ईमानदारी और सहजता के प्रशंसक रहे हैं। नित्या रेड्डी फिल्म का एक अहम किरदार है और इस भूमिका के लिए हमें उनसे बेहतर अभिनेत्री नहीं मिल सकती थी। उन्हें फिल्म से जोड़ना हमारे लिए बेहद खुशी की बात रही है और हम दर्शकों को इस भूमिका में उन्हें देखने का इंतजार कर रहे हैं।'



राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बन रही 'ओम: चैप्टर 1' में धनुष और ममूटी के साथ साई पल्लवी, श्रीलीला और नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। आरटेक स्टूडियोज और वंडरबार फिल्म्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही एक एक्शन थ्रिलर यानी रोमांच और जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म है। साई पल्लवी के परिचय टीजर के साथ निर्माताओं ने 'ओम: चैप्टर 1' की दुनिया की एक और झलक पेश की है।

ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई प्रियंका चोपड़ा की शॉर्ट फिल्म 'वी वर हियर'



अभिनेत्री और निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस की भारतीय शॉर्ट फिल्म 'वी वर हियर' को ऑस्कर की रेस में शामिल होने के लिए योग्य हो गई है। इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए प्रियंका ने कहा कि यह फिल्म एक समकालीन और महत्वपूर्ण विषय को नए तथा दिलचस्प अंदाज में प्रस्तुत करती है। प्रियंका चोपड़ा जोनस इस फिल्म से कार्यकारी निर्माता के रूप में जुड़ी हैं। शॉर्ट फिल्म 'वी वर हियर' एक मॉक्यूमेंट्री है, जो भारत के एक छोटे शहर में रहने वाले तीन ऐसे बुजुर्गों की कहानी दिखाती है, जो एआई के बढ़ते प्रभाव का विरोध करने के लिए घरेलू उपकरणों का रूप धारण कर लेते हैं। फिल्म को कई बड़े शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलों में अवॉर्ड मिल चुके हैं। पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल शॉर्टफेस्ट में 'बेस्ट लाइव-एक्शन शॉर्ट फिल्म' और 'बेस्ट कॉमेडी शॉर्ट' का पुरस्कार जीतने के बाद यह फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल होने के योग्य हो गई है। अभिनेत्री-प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा जोनस ने कहा, 'यह फिल्म एक ऐसे विषय पर मजेदार अंदाज में बात करती है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। मैं इस क्रिएटिव टीम को सपोर्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर तुरंत तैयार हो गई, ताकि उनकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।'



बॉलीवुड में किसी को किसी की कद्र नहीं



मनोज बाजपेयी इन दिनों बॉलीवुड से कुछ ज्यादा ही नाराज चल रहे हैं। चार बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीत चुके मनोज की पिछली दो फिल्में 'लास्ट मैन इन टावर' और 'गर्वनर' बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई हैं। इन दिनों वह नेटफ्लिक्स पर रिलीज अपनी फिल्म 'गजब रात' को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि, इस फिल्म को भी बहुत अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं। इस बीच 57 साल के एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री को 'एक बड़ा परिवार' मानने वाली आम धारणा को चुनौती दी है। 'गजब रात' के प्रमोशन के दौरान मनोज बाजपेयी ने कहा कि 'यह इंडस्ट्री बकवास है' और यहां किसी को किसी की कोई कद्र नहीं है।

फिल्म इंडस्ट्री कोई परिवार नहीं, ये भ्रम है

बातचीत में मनोज बाजपेयी ने कहा, 'अगर आप मुझे एक उदाहरण मानना चाहें, तो मैं एक उदाहरण हूं। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसका हिस्सा हूं। जरूरी नहीं कि आप बांद्रा से ही हों। आप मलाड में रहकर भी एक्टिंग कर सकते हैं। अहम बात यह है कि आप जो भी करें, वह अच्छा हो। बाकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में कोई 'परिवार' या 'बिरादरी' जैसी चीज नहीं होती। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि यह इंडस्ट्री एक परिवार है। यह किसी परिवार की तरह नहीं है। सबके ऑफिस अलग-अलग हैं, कोई किसी के साथ पार्टी नहीं करता और अगर किसी को किसी की फिल्म पसंद आ जाए, तो भी कोई फोन करके तारीफ नहीं करता।'

यहां कोई किसी की सफलता से खुश नहीं होता

'गजब रात' एक्टर मनोज बाजपेयी ने दो टूक कहा कि इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर किसी दूसरे की सफलता देखकर खुश नहीं होता। कोई भी डायरेक्टर खुद को दूसरे निर्देशक से कम नहीं समझता। कोई भी प्रोडक्शन हाउस किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस को ज्यादा पैसे कमाते देखकर खुश नहीं होता। इसलिए, इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए।
मैं काम करता हूं, पैसे लेता हूं और घर जाता हूं
साल 2024 में ओटीटी पर रिलीज 'गुलमोहर' के लिए नेशनल अवॉर्ड पाने वाले मनोज बाजपेयी कहते हैं, 'आप अकेले आए हैं और जब आप जाएंगे, तब भी अकेले ही जाएंगे। वैसे, इस तरह की सलाह देने के लिए मैं शायद सही इंसान नहीं हूं। मैं आपको पहले ही यह डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि मैं किसी को भी इस तरह से नहीं मानता। मैं अपना काम करता हूं, अपने पैसे लेता हूं और घर वापस आ जाता हूं।'

इंडस्ट्री में कोई भाईचारा नहीं कोई मदद के लिए नहीं आता

'सत्या' में भीखू म्हात्रे के किरदार से सिनेमा की दुनिया में चमकने वाले मनोज बाजपेयी ने आगे बताया कि वे अपने काम के तरीके पर न तो आलोचना का असर पड़ने देते हैं और न ही तारीफ का। वह कहते हैं, 'अगर आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, तो कृपया अपने घर पर ही रहें। अगर वे मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं, तो मैं उन्हें सुनने के लिए बहुत दूर रहता हूं। इसलिए कोई लगाव नहीं है। मुझे छोड़िए, इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति, चाहे वे कितनी भी बार यह कहें कि 'इंडस्ट्री एक परिवार है' - नहीं, यह सब बकवास है। यहां कोई भाईचारा नहीं है। हम सभी अपनी-अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आपको पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। अगर कोई आपकी मदद के लिए आ जाए, तो समझ लीजिए कि वह आपका एक अच्छा दिन था, बस इतना ही।'



देशहित में अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं: विधायक सुनील सोनी

'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत रायपुर दक्षिण में प्रबुद्धजन संगोष्ठी संपन्न

विरोध की खातिर अमर्यादित भाषा का प्रयोग अत्यंत निराशाजनक: सुनील सोनी

धारा 370 की समाप्ति और नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ ने विकास को दी नई गति; प्रबुद्धजनों ने किया मंथन

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

रायपुर। 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के अंतर्गत रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में सोमवार को एक भव्य प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने देशविरोधी व अराजक ताकतों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब विषय देशहित का हो, तब कुतर्क से नहीं बल्कि तर्क से बात होनी चाहिए। सत्ता हथियाने की होड़ में अराजकता फैलाकर राष्ट्र को क्षति पहुंचाने की कोशिश करने वालों के लिए देशहित में कोई स्थान नहीं है।



विरोध के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल निराशाजनक

विधायक सुनील सोनी ने कहा कि केवल विरोध करने की जिद में अमर्यादित भाषा का सहारा लेना अत्यंत चिंताजनक और निराशाजनक है। उन्होंने कहा, ÷कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और जब संसद में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए धारा 370 व 35 को समाप्त किया गया, तब पूरे देश को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ खड़ा होना चाहिए था। आज देश की सीमाएं पहले से कहीं अधिक सुरक्षित व व्यवस्थित हैं और भारत नई गति से प्रगति पथ पर अग्रसर है।÷ उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की पुरानी पहचान समाप्त हो चुकी है और राज्य तेजी से नक्सलमुक्त होकर शांति की राह पर बढ़ रहा है।

विकसित भारत के निर्माण में युवा पीढ़ी की सहभागिता जरूरी

विधायक ने आगाह करते हुए कहा कि सकारात्मक माहौल में कुछ लोग लगातार नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। आज जब पूरा राष्ट्र 'विकसित भारत' और 'सशक्त-स्वदेशी भारत' के संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर है, तब अवरोध के बजाय सहयोग की भावना आवश्यक है। विश्व के कई देश आज अराजकता की आग में झुलस रहे हैं, इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी को आगे आकर राष्ट्रनिर्माण में अपना योगदान देना होगा और लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाना होगा।

सैकड़ों प्रबुद्धजन और कार्यकर्ता रहे उपस्थित

संगोष्ठी में मुख्य वक्ता शशांक शर्मा और भाजपा रायपुर जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने भी विषय पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी पांचों मंडलों के मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा व युवा मोर्चा के पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सामाजिक प्रमुख, अधिवक्ता, चिकित्सक, इंजीनियर और अनेक समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

घर बैठे एक कॉल पर 99त्न मामलों का निराकरण, साय सरकार के सुशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण: डॉ. किरण बघेल

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. (श्रीमती) किरण बघेल ने रायपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित 'जन समस्या निवारण कॉल सेंटर' की सफलता को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के ÷सुशासन और अंत्योदय÷ के संकल्प का जमीनी प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि साय सरकार में आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध व पारदर्शी समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।



दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति, 42 विभागों का एक मंच पर समाधान- भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था में आम जनता को एक छोटे से काम के लिए बाबू की टेबल से लेकर अफसरों के दफ्तरों तक चक्कर काटने पड़ते थे और फाइलें महीनों अटकी रहती थीं। आज व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है और मात्र एक फोन कॉल पर 42 विभागों से जुड़ी समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर में अब तक दर्ज कुल 16,305 शिकायतों में से 16,156 शिकायतों (लगभग 99 प्रतिशत) का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

तय समय-सीमा और तय जवाबदेही- प्रणाली की कार्यप्रणाली को रेखांकित करते हुए डॉ. बघेल ने कहा कि कॉल सेंटर में प्रत्येक शिकायत के लिए जवाबदेही तय की गई है। आपातकालीन प्रकृति के मामलों में अधिकतम 48 घंटे और सामान्य मामलों में 3 दिन की अनिवार्य समय-सीमा के भीतर समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। इससे प्रशासनिक मशीनरी में तत्परता और जवाबदेही बढ़ी है।

संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल- कॉल सेंटर की तकनीकी दक्षता के साथ उसके मानवीय दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने एक घटना साझा की। उन्होंने बताया कि महीनों से प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे एक मूक-बधिर बच्चे के परिवार की पीड़ा को कॉल सेंटर की विशेष टीम ने समझा। टीम ने वीडियो कॉल के माध्यम से सांकेतिक भाषा (स्द्धद्दठ्ठ स्ठ्ठद्दठ्ठद्दद्बद्दद्दद्म) में संवाद किया और तत्परता दिखाते हुए महज दो दिनों के भीतर बच्चे का निवास प्रमाण पत्र बनवाकर सौंपा। डॉ. किरण बघेल ने नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबरों-9977222564, 9977222574, 9977222584, एवं 9977222594-का पूरा लाभ उठाएं और अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाएं।

राहुल गांधी पहले 'शिवतत्त्व' समझें, सनातन और छत्तीसगढ़ के अपमान पर देश से माफी मांगे कांग्रेस: पुरन्दर मिश्रा

शिव का तांडव गहन आध्यात्मिक दर्शन, इसे राजनीतिक अराजकता से जोड़ना निंदनीय: पुरन्दर मिश्रा

राज्य स्थापना दिवस का बहिष्कार कर कांग्रेस ने किया 3 करोड़ छत्तीसगढ़वासियों की अस्मिता पर कुठाराघात

रामलीला मैदान की क्षमता महज 45 हजार, 10 लाख की भीड़ का दावा हास्यास्पद

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक पुरन्दर मिश्रा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले 'शिवतत्त्व' और उसके गहन मर्म को समझना चाहिए। भगवान शिव का तांडव सनातन धर्म का सर्वोच्च आध्यात्मिक दर्शन है, कोई राजनीतिक नारा या अराजकता का माध्यम नहीं। सनातन संस्कृति को बार-बार आहत करने और छत्तीसगढ़ की अस्मिता का अपमान करने के लिए कांग्रेस को देश और प्रदेशवासियों से अविलंब सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।



शिव की बारात समरसता का प्रतीक, अराजकता का नहीं- विधायक पुरन्दर मिश्रा ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की बारात सामाजिक समरसता, सद्भाव और एकात्मता की अनुपम मिसाल है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को स्थान प्राप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया, ÷हम भगवान शिव की बारात में सहर्ष शामिल होंगे, लेकिन तांडव जैसे पावन और गूढ़ आध्यात्मिक दर्शन को राजनीतिक अराजकता से जोड़ने की विकृत मानसिकता का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता।÷ राहुल गांधी द्वारा धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक दुरुपयोग सनातन आस्था पर सीधा प्रहार है।

स्थापना दिवस का बहिष्कार छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान- कांग्रेस द्वारा 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के बहिष्कार पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि इस गौरवशाली दिन से मुंह मोड़कर कांग्रेस नेताओं ने 'छत्तीसगढ़ महतारी' और प्रदेश के तीन करोड़ नागरिकों की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह दोहरा रवैया बेहद शर्मनाक है। एक ओर 1 नवंबर 1984 का सिख नरसंहार देश के इतिहास का काला अध्याय है, जिसकी जिम्मेदारी और अपने नेताओं की संदिग्ध भूमिका पर कांग्रेस आज तक चुप्पी साधे हुए है, वहीं दूसरी ओर वह राज्य के उत्सव का बहिष्कार कर अलगाववादी मानसिकता का परिचय दे रही है।

रामलीला मैदान में 10 लाख की भीड़ का दावा सफेद झूठ- कांग्रेस द्वारा रामलीला मैदान के आयोजन में 10 लाख लोगों के जुटने के दावों को आड़े हाथों लेते हुए पुरन्दर मिश्रा ने कहा कि जिस मैदान की कुल क्षमता ही लगभग 45 हजार है- जिसमें मंच और सुरक्षा व्यवस्था के चलते बैठने की जगह और कम हो जाती है-वहां लाखों की संख्या का दावा करना जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कांग्रेस को जनता के सामने इस तरह के भ्रामक आंकड़े पेश करने से बाज आना चाहिए।

देश को अराजकता नहीं, राष्ट्रहित चाहिए- मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का पूरा राजनीतिक इतिहास सत्ता में रहते हुए आपातकाल लगाने और सत्ता से बाहर होने पर भ्रम व अस्थिरता फैलाने का रहा है। आज जब देश को सकारात्मक विमर्श और एकता की जरूरत है, तब कांग्रेस केवल राजनीतिक टकराव को हवा दे रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि सनातन संस्कृति, सिख समाज के मान-सम्मान और छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

भूपेश सरकार के कार्यकाल में डीए-डीआर के बकाये को भूल गए विकास उपाध्याय : वीरेन्द्र नामदेव



रायपुर। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय द्वारा छत्तीसगढ़ की साय सरकार की ओर से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के निर्णय को आधा-अधूरा न्याय बताने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि विकास उपाध्याय को कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की बात करने से पहले कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के पांच साल के कार्यकाल का भी स्मरण करना चाहिए। उस दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत नहीं मिली और बड़ी मात्रा में एरियर का भुगतान लंबित रहा। नामदेव ने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान में देरी तथा एरियर से वंचित रखने की समस्या की शुरुआत वर्ष 2019 में भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की किस्तों की घोषणा किए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने आदेश जारी करने में विलंब किया और कई मामलों में लाभ देय तिथि के बजाय आदेश जारी होने की तिथि से दिया। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके वास्तविक अधिकार का लाभ समय पर नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक के कांग्रेस शासनकाल में महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की विभिन्न किस्तों के भुगतान में लगातार विलंब हुआ। महासंघ के आकलन के अनुसार, इस अवधि में लगभग 34 से 40 माह तक के एरियर का बकाया बना, जिसका पूरा भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। यही विलंबित भुगतान की परंपरा आगे भी जारी रही और अब विभिन्न लंबित किस्तों को मिलाकर कुल बकाये का आंकड़ा लगभग 99 माह तक पहुंचने की स्थिति बताई जा रही है। नामदेव ने स्पष्ट किया कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ वर्तमान साय सरकार द्वारा घोषित 2 प्रतिशत महंगाई राहत को पर्याप्त नहीं मानता। महासंघ की मांग है कि केंद्र सरकार के अनुरूप जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत तथा जुलाई 2026 से देय 3 प्रतिशत की वृद्धि मिलाकर कुल 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत, वर्तमान दर 63 प्रतिशत करते हुए, संपूर्ण एरियर सहित तत्काल स्वीकृत और भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों का प्रश्न किसी दल विशेष की राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। यदि विकास उपाध्याय वास्तव में कर्मचारियों और पेंशनरों के हितैषी हैं, तो उन्हें कांग्रेस शासनकाल में लंबित रखे गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर पर भी अपनी स्पष्ट राय रखनी चाहिए। केवल वर्तमान सरकार के निर्णय की आलोचना करने से पूर्ववर्ती सरकार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। नामदेव ने कहा कि पेंशनरों को न कांग्रेस शासनकाल में उनका पूरा हक मिला और न ही वर्तमान में उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप भुगतान हो रहा है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, संतोषी नगर में 'सुरक्षित बचपन अभियान' के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रायपुर। जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में माननीय जेएमएफसी कुमारी प्रज्ञा सिंह एवं कुमारी श्रद्धा भगत ,पैनल अधिवक्ता अंकिता मिश्रा और थाना टिकरापारा के वरिष्ठ आरक्षक भारतेंद्र साहू ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, पॉक्सो एक्ट, बाल शोषण एवं बाल विवाह की रोकथाम संबंधी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां दीं। वक्ताओं ने अपने संबोधन में बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, किसी भी अनुचित घटना पर चुप न रहने तथा बिना भय अपनी बात अभिभावकों एवं शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सुरक्षित बचपन एवं बाल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा, प्राचार्य श्रीमती वंदना ओझा, प्रदान करना।



अच्छे-बुरे स्पर्श, साइबर सुरक्षा एवं सहायता। हेल्पलाइन नंबर आपातकालीन 112, महिला हेल्पलाइन181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930 की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिकाएं गीतिका शर्मा, उपासना साहू, लक्ष्मी देवांगन और ओमेश्वरी साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन पैरालीगल वॉलिंटियर्स सचिन पांडे एवं शंकर साहू ने किया। उद्देश्य: बच्चों को जागरूक, आत्मविश्वासी एवं सुरक्षित वातावरण

किसानों के खाते में 1.5 लाख करोड़ और महिलाओं को सम्मान निधि मिलना कांग्रेस को नहीं पच रहा: अमित चिमनानी

तरुण बन्छोर- जनता के गोठ

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सीए अमित चिमनानी ने कांग्रेस के बयानों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश के किसानों और महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण कांग्रेस को पच नहीं रहा है। किसानों को धान का 3,100 रुपये एकमुश्त मूल्य मिलना और महिलाओं के खाते में हर माह 1,000 रुपये की सम्मान राशि पहुंचना विपक्ष के लिए असहनीय हो गया है।



किसानों और महिलाओं के खातों में सीधे पहुंची सहायता राशि- अमित चिमनानी ने कहा कि भाजपा सरकार ने तीन साल से भी कम समय में किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की है। वहीं, 'महतारी वंदन योजना' के तहत प्रदेश की माताओं-बहनों को बिना किसी देरी के हर महीने राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में जमा की जा चुकी है।

20 लाख आवास और अधोसंरचना के लिए रिकॉर्ड बजट- प्रदेश प्रवक्ता ने विकास कार्यों का ब्योरा देते हुए बताया कि राज्य में 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अब तक का ऐतिहासिक बजट आवंटित किया गया है, जिसमें केवल सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए एक ही वर्ष में 9 हजार करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल में कर्ज लेकर भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस आज झूठे आंकड़े गढ़कर किसानों और महिलाओं के कल्याणकारी बजट का विरोध कर रही है।

आंकड़ों के साथ दी वित्तीय स्थिति की जानकारी- कांग्रेस द्वारा वित्तीय स्थिति पर उठाए जा रहे सवालों का तथ्यात्मक जवाब देते हुए सीए अमित चिमनानी ने कहा कि सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरह संतुलित और मजबूत है:

- शुद्ध ऋण सीमा में: बीते 3 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा केवल 49,279 करोड़ रुपये का ही शुद्ध ऋण लिया गया है। - FRBM नियमों का पालन: यह ऋण FRBM एक्ट द्वारा तय सीमा (GSDP के 3%) के

एक राज्य, एक समान DA" लागू करे सरकार, केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं एरियर्स भुगतान की मांग

दीपावली पूर्व लंबित ड्ढ एरियर्स सहित भुगतान नहीं होने पर प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन की चेतावनी

रायपुर।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) स्वीकृत करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को विस्तृत मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। फेडरेशन ने प्रदेश में महंगाई भत्ते के लिए ÷एक राज्य, एक समान ड्ढ÷ की व्यवस्था लागू करने तथा लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स की संपूर्ण राशि कर्मचारियों के GPF खाते में समायोजित करने की मांग की है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी प्रदेश की विकास यात्रा एवं सुशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद महंगाई भत्ते के मामले में कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से लाभ नहीं मिलना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महंगाई पूरे देश में समान रूप से प्रभाव डालती है, ऐसे में महंगाई भत्ते के भुगतान में अलग-अलग मापदंड अपनाना कर्मचारियों के साथ न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के माध्यम से कर्मचारियों की अपेक्षाओं को बल मिला था। सरकार के लगभग तीन वर्ष पूर्ण होने की ओर अग्रसर होने के बावजूद केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने के संबंध में स्थायी नीति निर्धारित नहीं किया जाना कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न कर रहा है। फेडरेशन ने मध्यप्रदेश सरकार की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ में भी महंगाई भत्ते का लाभ वास्तविक देय तिथि से दिया जाना चाहिए। फेडरेशन ने दीपावली के पूर्व लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता जुलाई 2026 से स्वीकृत करने तथा वर्तमान में स्वीकृत 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आदेश में संशोधन कर जनवरी 2026 से लाभ प्रदान करने की मांग की है। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण घटक है, न कि शासन की कोई कृपा अथवा अनुदान। कर्मचारियों एवं पेंशनरों को समय पर महंगाई से राहत देना शासन की जिम्मेदारी है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की दर घोषित किए जाने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी बिना अनावश्यक विलंब के उसी देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत स्वीकृत करने की स्थायी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार मध्यप्रदेश की भांति दीपावली के पूर्व महंगाई भत्ते का एरियर्स सहित भुगतान नहीं करती है, तो फेडरेशन प्रदेशभर में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। फेडरेशन ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों की अनदेखी होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। फेडरेशन को पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए दीपावली के पावन पर्व पर आर्थिक राहत प्रदान करने का संवेदनशील निर्णय लेगी। कर्मचारियों की जायज अपेक्षाओं का समयबद्ध समाधान शासन एवं कर्मचारियों के मध्य विश्वास के संबंध को और मजबूत करेगा। उक्त मांगों का समर्थन श्री कमल वर्मा, श्री चंद्रशेखर तिवारी, श्री पवन कुमार शर्मा, श्री बी.पी. शर्मा, श्री रोहित तिवारी, श्री राजेश चटर्जी, श्री पंकज पाण्डेय, श्री संजय सिंह, श्री आर.के. रिछारिया, श्री सतीश मिश्रा, श्री जी.आर. चंद्रा, श्री केदार जैन, श्री रविन्द्र राठौर, श्री कैलाश चौहान, श्री रमेश ठाकुर, श्री टारजन गुप्ता।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक,संपादक-शुभम वर्मा द्वारा मकान नंबर 411, देवनगर, आदिवासी छात्रावास के सामने, शिव शंकर होटल के पीछे महादेव घाट रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित एवं छत्तीसगढ़ प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स अनंत विहार कालोनी,दलदल सिवनी मार्ग -मोवा रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित। (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) फोन:-9300870270, 9425520408 jantakegoth@gmail.com